RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

इंसान को कठिनाईयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि सफलता का

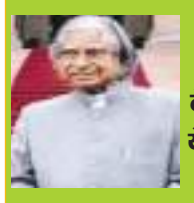

आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

वर्ष-04, अंक - 18 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 03 फरवरी 2022 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

बजट अमृतकाल का हलाहल मध्यवर्गी को

माही की गूंज, झाबुआ।

देश की वित्मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश पेश बजट 2020-23 को अमृतकाल का बजट बतलाया है, लेकिन पूरे बजट में देश की सर्वाधिक आबादी मध्यमवर्गी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। जिसके बाद देश का वह मध्यमवर्गी जो ईमानदारी के साथ टैक्स भरता है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है।

इस वर्ष का बजट कैसा रहेगा इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईशारों-ईशारों में ही अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कह दी थी, जिसमें उन्होंने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को देश को खोखला करने वाला बताया था और देश के नागरिकों को कर्तव्य बोध की प्रेरणा देते हुए कहा कि, कर्तव्यबोध से भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है।। जिस प्रमुख मुद्दे (भ्रष्टाचार) पर 2014 में भाजपा सरकार में आई आज 7 साल बाद भी वह मुद्दा यथावत है तो इसमें कमजोरी किसकी है...?

बजट यह शब्द अपने आप में अनोखा है, आम आदमी को देश के बजट से ज्यादा अपने घर के बजट की चिंता रहती है और वार्षिक बजट के स्थान पर कई लोगों के लिए मासिक बजट और कई लोगों के लिए दैनिक बजट को मैनेज करना टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे मध्यमवर्गी व निम्न मध्यमवर्गी लोगों के लिए देश का बजट केवल क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ यह जानने भर तक ही सीमित रहता है। ऐसे में आज के बजट में आम आदमी यह सोचने पर विवश है कि, रत्न व आभूषण सस्ते होने व छाता महंगा होने से उसका क्या फायदा होने वाला है...?

पेट्रोलियम पदार्थ महंगा और मोबाइल फोन चार्जर सस्ता होने से उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी...? जबकि मोबाइल कंपनियां अपने डाटा पैक के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है जिस पर सरकार का न कोई ध्यान है न ही कोई कंट्रोल।

कांग्रेस का मोदी सरकार पर शुरू से ही यह आरोप रहा है कि, मोदी सरकार सूट-बूट की सरकार है और कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इस बजट से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि, सरकार को केवल उद्योगपतियों की चिंता है, मध्यमवर्गी की नहीं, जबकि मध्यमवर्गी ने सरकार

को 2.9 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स भरा।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार है

टैक्सः अमृतकाल के बजट को सरकार आजादी के 100 साल का ब्लू प्रिंट बतला रही है, टैक्स स्लैब मै कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की धारा 80 सी में भी कोई छूट नहीं दी गई है, यानी ज्यादा बचत करने पर भी सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला है।

नौकरीः सरकार का दावा है कि, 60 लाख नई भर्तीया की जाएगी जिसमें कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले भी लाभान्वित हो सकते हैं, इनमें 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के तहत दी जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि, बेरोजगारो के लिए तत्काल कोई राहत नजर नहीं आ रही है। मनरेगा बजट में कटौती से लोगों के रोजगार के अवसर कम होंगे। कोविड काल में 60 प्रतिशत लोगों की आय घटी है, उसके लिए सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी जा रही है।

घरः दूसरा मकान लेने पर मिलने वाली ब्याज में छूट को खत्म कर दिया है, इसमें मध्यमवर्गी को दूसरा घर बनाने पर 1.5 लाख के ब्याज की छूट का नुकसान होगा। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 48 हजार करोड़ के हाउसिंग बजट में मध्यमवर्गी के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है।

बिजनेसः मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट की मियाद 1 साल बढ़ाई गई है, कोरपोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से कम कर के 15 प्रतिशत किया गया है, जिसमें घर, गैर सूचीबद्ध स्टॉक जैसी संपत्तियों के हस्तांतरण में यह काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

खेतीः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं बढ़ाई गई है लेकिन खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से खेती का सामान सस्ता हो सकता है, ऑर्गेनिक खेती और ऑयल सीड को बढ़ावा देकर कमाई का रास्ता निकालने का प्रयास किया है, वही आधुनिक खेती व डिजिटल खेती को प्रोत्साहन दिया गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्मः डिजिटल क्रांति को कोविड-19 संक्रमण काल में बहुत अधिक बढ़ावा मिला है और सरकार ने भी इसे माना है और इस क्षेत्र में बजट के कोई प्रावधान किए हैं।..... वन क्लास वन टीवी चैनल के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए चैनल 12 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे, जिसमें कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना होगी, जिसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और पैसो व समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा आरबीआई डिजिटल रूपी जारी करेगा, ब्लॉक चैनल और अन्य टेक्नोलॉजी के जरिए इसे पेश किया जाएगा, यह दो तरह की होगी रिटेल और होलसेल, इसे देश की सॉवरेन करेंसी में भी बदला जा सकेगा, इससे डिजिटल इकोनामी मजबूत होगी और करेंसी प्रबंधन आसान और सस्ता होगा।

गति शक्तिः इस योजना में अगले 25 साल के सपने संजोए गए हैं। इसके अंतर्गत 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, इसमें रेलवे, सड़क, पेट्रोलियम-गैस, बिजली, टेलीकॉम, विमानन और औद्योगिक पार्क को शामिल किया जाएगाऔर 109 नए एयरपोर्ट, 51 हेलीपैड, 12 वाटर एरोड्रोम, 2 लाख किलोमीटर हाईवे, 200 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल और नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रावधान है।

नारी शक्तिः मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी को नया रूप दिया जाएगा, 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने की योजना है। 20 हजार 105 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

कुल मिलाकर सरकार की ओर से कहा गया है कि, यह दूरदर्शी बजट है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वे भविष्य को लेकर किए गए हैं। अब देखना यह है कि, सरकार में आम आदमी को जो सपने दिखाए वह कितने पुरे हो पाते हैं...?

विधानसभा चुनाव 2018 में हुए भ्रष्टाचार के जिंदा सबूत छोड़ गए अधिकारी

तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा हिसाब, नगर परिषद ने कहा नही मिली कोई राशि

माही की गूंज, झाबुआ।

वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में व्यवस्था के नाम पर हुए भारी भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा रहा, जबकि भ्रष्टाचार के जिंदा सबूत खुद तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी लिखित में छोड़ कर गए। आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण उर्फ दिलीप मालवीय द्वारा निकाली गई सूचना के अधिकार में जानकारी में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारीयो पर कार्रवाई नही की गई, जबकि मामले में अपराध दर्ज किया जाना था। मामले में पेट घुटने की और ही मुड़ता है वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योकि सारे प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ हुई शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नही हुई। हम यह भी बताएंगे कि, आखिर जॉच अधिकारी ने कैसे मामले में शिकायतकर्ता को गुमराह कर मामले को दबाया पर उससे पहले आपको प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से तत्कालीन कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने किस तरह इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले के सभी बूथों के लिए मध्यप्रदेश निर्वाचन भोपाल द्वारा चुनाव हेतु बूथों पर टेंट, लाइट, पानी और निर्वाचन में लगी टीम के भोजन, नाश्ते की व्यवस्था और प्रचार प्रासार के लिए लगभग 25 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया। लेकिन उक्त राशि का खर्च जिले की निर्वाचन शाखा से नही करते। बूथों पर लगने वाली पंचायतो और नगर परिषद को एजेंसी बनाकर उनसे राशि खर्च करवाई गई। जबकि व्यवस्था हेतु निर्वाचन आयोग की और से राशि का आवंटन हुआ था, जिसको तत्कालीन कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने खर्च करना बताकर हिसाब बनाकर मध्यप्रदेश निर्वाचन शाखा को भेजा गया। सूचना अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक/986/मा.निर्वा./लेखा/2019/झाबुआ 29 मार्च 2019 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल मध्यप्रदेश को पत्र व्यवहार कर आबंटित राशि के विभिन्न मदो से खर्च की गई राशि का ब्योरा दिया गया। चौकाने वाला तथ्य ये भी है कि, तत्कालीन कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने खर्च के लिए आई राशि मे से कुछ राशि शेष बताकर राशि समर्पण करने हेतु निर्देशित करना बताया गया। जबकि सूचना अधिकार में मिली झाबुआ, राणापुर, पेटलावद, मेघनगर नगर परिषद सहित जिले की ग्राम पंचायतों ने चुनाव 2018 में खर्च की गई राशि का भुगतान स्वयं द्वारा करना बताया साथ ही किसी प्रकार की राशि का आवंटन निर्वाचन शाखा द्वारा नही करना बताया गया। नगर पालिका झाबुआ द्वारा सूचना अधिकार में दी गई जानकारी 24/12/2020 को बताया गया कि, उनके द्वारा चुनाव के दौरान किन-किन व्यवस्था के लिए राशि खर्च की गई और ये भी जानकारी दी गई कि, झाबुआ से ऐसी किसी राशि का आवंटन नही किया गया। पूरी राशि परिषद द्वारा ही खर्च कि गई, सभी एजेंसियों से यही जानकारी दी गई। फिर तत्कालीन कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी द्वारा कौनसी राशि खर्च की गई और कहा कि गई ये जांच का विषय है और उसका खुलासा भी करेंगे। बरहाल मामला सीधा चुनाव आयोग और कलेक्टर से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन के हाथ पैर फुले हुए है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवीय ने बताया कि, अब तक मिले समस्त दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई लेकिन जाँच के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जबकि अधिकारीयो द्वारा दिए गए प्रमाणित दस्तावेजों से ही भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है।

नपा झाबुआ द्वारा दी गई जानकारी जिसमे विधानसभा चुनाव हेतु किसी राशि का आवंटन झाबुआ से नही होना बताया।

झाबुआ नगर पालिका द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा जो नगर पालिका के स्वयं के मद से खर्च की गई।

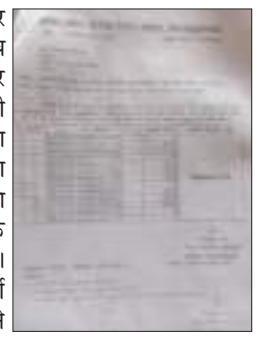

तत्कालीन कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारी भोपाल मध्यप्रदेश को खर्च की गई राशि का भेजा गया ब्यौरा

भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण नायक फिर आए अपने चरित्रहीन कृत्यों से सुर्खियों में

आखिर रजामंदी से हुआ था सम्मोहन या फिर जबरदस्ती हुआ महिला का शोषण पुलिस को करना चाहिए खुलासा

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा।

भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण नायक एक ऐसा नाम भाजपा के साथ जिले में चर्चित हो गया कि, वह अपनी बदनियत के साथ महिलाओं को देखता है वरन् जो महिलाएं उसके संपर्क में आती है उस महिला पर अपनी मोहिनी का जादू ऐसा चलाता है कि, महिला किसी तरह उसके चंगुल में आ जाए और वह उसका भोग कर सके। नतीजन सोशल मीडिया की क्रांति के दौरान भी खुले रूप से बिना किसी डर के गैर महिला से मोबाइल पर बदनियत से बातें करता, इतना ही नहीं गैर महिला से वीडियो कॉलिंग पर कभी बाथरूम में जाकर तो कभी किसी प्रकार से बात करने का कहता और गैर महिला से चरित्रहीन भाजपा जिला अध्यक्ष की मोबाइल पर हुई चर्चाएं भी सार्वजनिक हुई। जिसके बाद कई बार अपनी चरित्रहीनता के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सुर्खियों में आने के साथ ही भाजपा अध्यक्ष के पद पर आसिनी होकर अपने प्रभाव का प्रचार करते रहे है। एक मामले में अपनी बेटी की उम्र की महिला के साथ अपने अवैध संबंध प्रलोभन या दबाव जो भी हो ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन महिला से अवैध संबंध स्थापित करने के बाद महिला के साथ कुछ आपसी तालमेल बिगड़ने के कारण 4 जून को एक महिला ने एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक लक्ष्मण नायक ने एक से अधिक बार शोषण उसकी गाड़ी में किया कि, शिकायत की थी। वही 5 जून को ही लक्ष्मण नायक के साथ जिले की भांजगड़ी प्रथा का उपयोग कर मकान बनाकर देना व कुछ नगदी पैसे की बात होने के बाद महिला, जिस पत्रकार का सहयोग मांग रही थी उसी पत्रकार के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने के साथ फसाकर मामला दर्ज करवाया। साथ ही एक वीडियो भी जारी किया जबकि 4-5 जून की मध्य रात्रि में ही महिला ने पत्रकार को फोन कर लक्ष्मण नायक के साथ हुए समझौते की बात कह दी थी। साथ ही महिला ने यहां तक कह दिया था कि, लक्ष्मण नायक पर एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, अगर लक्ष्मण अपनी बात पर खरा नहीं उतरता है तो उसकी शिकायत फिर कर दूंगी। जिसका मय ऑडियो-वीडियो के साथ 10 जून 2021 को शीर्षक ''बेटी की हम उम्र महिला से लक्ष्मण नायक ने बनाएं नाजायज संबंध'' के साथ प्रकाशित किया था।

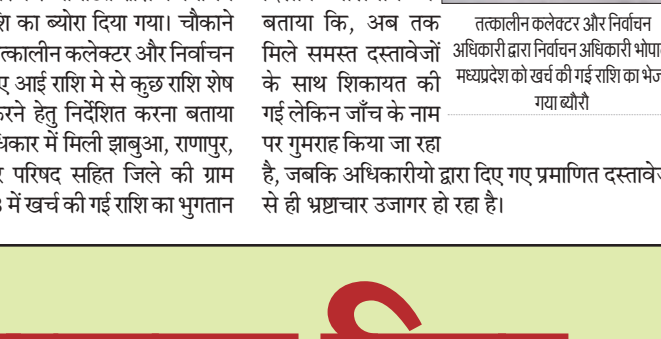

धमकाने, झूठी एफआईआर व लक्ष्मण नायक ने किया शोषण या आर्थिक लाभ हानि के साथ संबंध बनाकर की जा रही शिकायत...?

उक्त महिला ने एक बार फिर मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण नायक के विरुद्ध शिकायत कर जिले की राजनीति में गरमाहट लादी है। महिला ने अपने आप को झाबुआ तहसील की होना बताकर लक्ष्मण सिंह नायक जिला अध्यक्ष भाजपा द्वारा जान से मारने एवं शारीरिक शोषण करने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है।

शिकायत में महिला ने बताया, भाजपा जिलाध्यक्ष नायक ने तीन बार अलग-अलग स्थान पर खोटा काम किया, मना करने पर मेरे पति व मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में 4 जून 2021 को डाकघर के माध्यम से एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की थी, 5 जून को जब पुलिस अधीक्षक को शिकायत आवेदन देने मैं जा रही थी कि, फुलमाल के समीप से लक्ष्मण नायक ने अपहरण कर दूधेश्वर मंदिर के समीप पहाड़ियों में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे व मेरे पति को नीचे फेंक कर मार दूंगा कह कर दबाव बनाकर, लक्ष्मण नायक ने उसके साथ शारीरिक शोषण नहीं किया और पत्रकार ने डरा धमकाकर वीडियो बनाए का आवेदन बनाया व बंदूक की नोक पर मुझे रख वकील को बुलाकर कोरे स्टाम पर साइन करवाएं और पत्रकार के विरुद्ध थाने में ले जाकर मुझसे झूठे बयान करवाएं।

महिला ने शिकायत में बताया कि, आए दिन पुलिस हमारे घर आकर परेशान करती है और कहती है लक्ष्मण नायक के खिलाफ शिकायत मत करना नहीं तो तेरे पति को अंदर कर देंगे। के साथ महिला ने धमकाने, पत्रकार के विरुद्ध झूठी एफआईआर करवाने, उसके साथ शारीरिक शोषण होने एवं न्यायालय में ले जाकर झूठे बयान करवाने के साथ नायक के इशारे पर पुलिस द्वारा डराने धमकाने की शिकायत दर्ज की है।

माही की गूंज नहीं पूर्व में उक्त महिला की शिकायत एवं बाद में आपसी समझौते के संबंध में 10 जून, 17 जून, 24 जून को समाचार प्रकाशित किए थे।

क्या पुलिस अब भी मामले को अंधर में रखेगी या अपना जमीर जगा कर जांच करेगी...?

उक्त शिकायत के बाद पुलिस अब भी मामले में ढुल मूल रवैया रखेगी या फिर मामले में लक्ष्मण नायक और महिला के बीच राजी मर्जी के साथ आपसी संबंध थे...? डरा धमकाकर महिला की शिकायत अनुसार लक्ष्मण नायक ने महिला के साथ शोषण किया...? आर्थिक लाभ पाने के लिए महिला ने लक्ष्मण नायक से आपसी संबंध बनाए थे...? दोनों के आपसी संबंध के साथ लक्ष्मण नायक ने कोई प्रलोभन महिला को दिए जिस पर लक्ष्मण नायक वह भरपाई नहीं कर पाया, जिसके चलते पूर्व में या वर्तमान में पुलिस को शिकायत की गई ? जो भी हो मामले के खुलासे के साथ महिला, पुलिस को गुमराह कर रही है तो महिला के विरूद्ध मामला दर्ज हो या महिला की शिकायत सत्य है तो भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण नायक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जिला एवं प्रदेश की जनता को उक्त कृत्यों का खुलासा जरूर करना चाहिए।

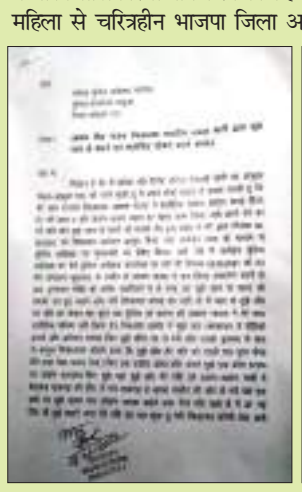

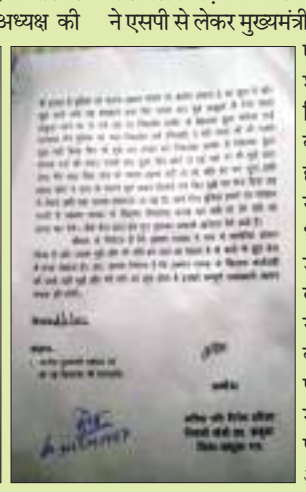

गौ-हत्यारों को देते संरक्षण तो बेगुनाह को अपराधी की तरह पुलिस दे रही यातना

गौ-रक्षा करने वाले व आदिवासी प्रताड़ना का विरोध करने वाले संगठनों का देखकर भी अनदेखी करना कई सवालों को कर रहा खड़ा

माही की गूंज, खवासा/भामल। नारयण पालरा

थांदला थाने की खवासा चौकी अंतर्गत पिछले दिनों एक ऐसा मामला आया जिसमें माही की गूंज ने पिछले अंक 27 जनवरी को ''आखिर यह कैसी देश भक्ति जनसेवा...? अपनी मां कहीं जाने वाली गाय के हत्यारों को ही संरक्षण दे रही पुलिस'' व ''गौ माता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करने वाले भाजपा के साथ हिंदू संगठन का मौन भी कई सवाल कर रहा खड़े'' के शिर्षक के साथ प्रकाशित किया था। जिसमें प्रमुखता के साथ खुलासा किया था कि, किस तरह से खवासा पुलिस ने मय गौ माता के मांस के साथ अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाने हेतु पुलिस के पास पीड़ित टीटा भुरजी जाति देवदा निवासी परवाड़ा लिखित रिपोर्ट के साथ मामला दर्ज करवाने हेतु पुलिस चौकी पहुंचा। लेकिन 3 दिनों तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और तीसरे दिन गाय की चोरी कर गाय की हत्या कर उसके मांस का बटवारा करने वाले आरोपी को पुलिस पकड़ कर लाई और पुलिस से आरोपित की ऐसी साठ-गाठ हुई की अपनी मां कहीं जाने वाली गौ माता के हत्यारों के साथ भांजगड़ी कर आपसी समझौता के साथ मामले को किस तरह से रफा-दफा किया, हमारी कलम ने पूरी बेबाकी के साथ खुलासा किया कि, पुलिस किस तरह से गौ हत्यारों को संरक्षण दे रही है। वही हमारे खुलासे के पूर्व भी कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता व भाजपाइयों को मामले की जानकारी लगने के बाद भी मोन रहे। इतना ही नहीं माही की गूंज में गौ माता की हत्या व मामले का पूरा खुलासा होने के बाद भी वो सभी हिंदू संगठन जो गौ रक्षा की बात कर अपराधियो के विरुद्ध मामला दर्ज करवाने के लिए तत्पर होकर अपने आप को हिंदूवादी का संगठन बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते है, सिद्ध करते हुए पूरी तरह से मोन है। इतना ही नही थाने या चौकी में जाकर एक ज्ञापन तक गौ हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नहीं दिया और नहीं पुलिस की उक्त मामले में की गई कारस्तानियो का विरोध किया।

यहां यही बात आम चर्चा में निकल कर आ रही है कि, अगर कोई समाज विशेष के द्वारा गौ हत्या का मामला सामने आता तो, पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती और मामला दर्ज होने के बाद भी गौ रक्षा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेखने वाले हिंदू संगठन भी सख्त कार्रवाई की मांग कर अपना मोर्चा जगह-जगह खोल देते।

उक्त मामले में यहां पुलिस को त्वरित मामला दर्ज कर मामले की जांच के साथ आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भिजवाना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।

किसी गरीब की रोजी रोटी व आशियाना को छिना जाए तो उसकी पीढ़ा को वही जान सकता है साहब

वही एक खवासा चौकी के अंतर्गत ऐसा मामला आया जिसमें किसी भी प्रकार से पीड़ित की कोई गलती नहीं थी और न कोई रिपोर्ट व एफआईआर और बिना एफआईआर के पुलिस ने अपराधी मानकर लात-घुसो के साथ मारकर चौकी पर ले आई। वहीं जब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो पिता को उठाकर पुलिस ले आई और हवालात में डाल दिया। मामले में लक्ष्मण पिता नारजी डामोर निवासी वडलीपाड़ा (भामल) जिसकी भूमि सर्वे क्रमांक 202, 250 जिसपर वर्षो से पिढी दर पिढा खेती कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। एक्सप्रेस वे निर्माण में भूमि का अधिग्रहण होकर उक्त सर्वे क्रमांक को सरकारी भूमि बताकर मुआवजा नहीं मिलने पर, लक्ष्मण की तरह कई पीड़ित ग्रामीण के आशियाने व रोजी-रोटी छिनने व उसके वाजिब मुआवजे नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठकर एक्सप्रेस वे निर्माण को कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास किया था। जिसके बाद एक्सप्रेस वे कार्य करने वाली जीआर इंफ्रा कंपनी पुलिस व प्रशासन का सहयोग लेकर कई तरह की सूचनाएं लिखित व मौखिक में देकर ग्रामीणों को दबाने का प्रयास किया था। लेकिन ग्रामीण अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए अपनी मांग पर अड़े रहे थे। आखिरकार जीआर इंफ्रा ग्रामीणों से समझौता कर व स्थानीय पंचायतों से तालमेल कर मामले के समाधान के रूप में किसी को पूरी-पूरी राशि देने की बात कही तो, किसी को कम मुआवजा देने के साथ स्थानीय पंचायत में ठहराव प्रस्ताव कर अन्य पट्टे की शासकीय भूमि को ग्रामीणो के नाम करने की सहमति बनी। इसी कड़ी में लक्ष्मण डामर की भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशि का 80 हजार देकर पंचायत में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1312 रकबा 0.48 हेक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत में 8 मार्च 2021 के ठहराव प्रस्ताव के साथ आपसी सहमति बन लक्ष्मण को जमीन दी गई।

- लक्ष्मण व पत्नि लिला बाई डामर गूंज को पुलिस की कारस्तानी व अपनी पीढा बताते हुए।

आपसी सहमति के दौरान जीआर इंफ्रा कंपनी के मुलाजिम मनोज कुमार, पवन मिश्रा, अजय पनावत के साथ थांदला पूर्व विधायक कलसिंह भाभर व राहुल भाभर के समक्ष तय हुआ कि, पंचायत द्वारा की गई ठहराव प्रस्ताव की भूमि ठेकेदार के द्वारा पूर्णतः उपजाऊ भूमि कर के देंगे, जिसके लिए जितना भी मिट्टी मटेरियल लगेगा वह खेत में डालकर देंगे। साथ ही लक्ष्मण एवं उसके पुत्र को टोल टैक्स पर 15 साल के लिए नौकरी करने हेतु प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे का आपसी अनुबंध भी हुआ।

अनुबंध से पलटा जीआर इंफ्रा, नुमाइंदों ने झूठी सूचना दी थी पुलिस को

अनुबंध के बाद कार्य की शुरुआत करने के बाद एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर चला और उसी दौरान लक्ष्मण डामर की भूमि पर कार्य कर उसकी भूमि में मिट्टी डालने पर मना कर दिया। वही नौकरी के अनुबंध से भी जीआर इंफ्रा के नुमाइन्दे मुकर गए, तो लक्ष्मण एवं अन्य साथी ने अपना विरोध जताया, जिस पर गांव के गणेश डामर, लीला पत्नी लक्ष्मण डामर, मोहन कटारा आदि के विरुद्ध चित्तौड़ी में सूचना रिपोर्ट अजय बनावत ने पुलिस चौकी में दी। उक्त सूचना रिपोर्ट के बाद भी ग्रामीण एवं जीआर इंफ्रा के मध्य आपसी समझौता होने के करीब 7 माह बाद अपने निजी स्वार्थ के साथ बिना सूचना रिपोर्ट के ही लक्ष्मण के पुत्र अमित को 24 दिसंबर को किसी बडे अपराधी की तर्ज पर लात घुस्से मारकर एवं कपड़े तक फाड़ कर जबरदस्ती पुलिस के वाहन में बिठाकर खवासा चौकी पर लेकर आए।

मामले में अमित की मां लीला बाई पति लक्ष्मण व परिवार ने आपत्ति जताई एवं माहौल की गहमा-गहमी ऐसी हुई कि, जीआर इंफ्रा के मुलाजिम अजय बनावत ने भी पुलिस को कहा कि, मैंने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई तो क्यों पकड़ कर बेगुनाहों को लेकर आए। इसके बाद खिसियानी बिल्ली की तर्ज पर पुलिस ने बिना किसी जवाब तलब के अमित को छोड़ा।

सीएम हेल्पलाइन पर पुलिस के विरुद्ध हुई शिकायत, बौखलाई पुलिस

जिसके बाद लीला पति लक्ष्मण ने 24 दिसंबर को ही झूठा अपराध पंजीबद्ध करने एवं गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने के संबंध में पुलिस के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। जिसके बाद पुलिस एसे बौखलाई कि, उसके पैर तले जमीन ही खिसक गई हो। सीएम हेल्पलाइन से शिकायत को कटवाने के लिए पुलिस के अधिकारियों का दुरुपयोग कर खवासा चौकी प्रभारी गणावा के साथ पुलिस स्टाफ वडलीपाडा पहुंची और लीलाबाई के पति लक्ष्मण को उठाकर किसी अपराधी को लेकर आते हैं उस तरह से लेकर आई और थांदला थाने पर लेजाकर अर्धनग्न कर लाकअप में डाल दिया। थाना प्रभारी कौशल्या चौहान के साथ चौकी प्रभारी ने सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। मामला जब माही की गूंज तक भी पहुंचा तो गूंज प्रतिनिधि की टीआई से बात करने के बाद पुलिस हरकत में आई और बेगुनाह लक्ष्मण को आधी रात को छोड़ दिया। उक्त वाक्ये की भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, वही 24 दिसंबर को हुई शिकायत में लक्ष्मण के बयान का झूठा हवाला देकर पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन से मामले का निराकरण भी कर दिया। मामले में जहां पीड़ित लक्ष्मण का परिवार हर किसी से मदद की गुहार लगाता रहा और एसपी तक मामले की शिकायत की परंतु आदिवासी हक की बात करने वाले आदिवासी संगठन लक्ष्मण एवं परिवार के साथ अभी तक खड़ा नहीं दिखाई दिया। वही एक गौ हत्या के मामले में पुलिस को तत्काल अपराधियों के विरूद्ध मामला दर्ज करना था और अपराधियों को संरक्षण दिया। दूसरे मामले में लक्ष्मण एवं परिवार किसी भी मामले में गुनहगार नहीं था पर पुलिस एक आम आदमी को गुनेहगार मान बेगुनाह को बार-बार थाने पर लाकर हवालात में डाल रही है। दोनों मामले में अपनी-अपनी जगह रोटियां सेकने वाले राजनीतिक संगठनों की चुप्पी कई सवालों को खड़ा कर रही है।

स्किल हब सेंटर का हुआ उद्घाटन, शाला छोड़ चुके छात्र-छात्राओं को मिलेगा लाभ

माही की गूंज, पेटलावद।

शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी शिशिर गेमावत द्वारा स्किल हब सेंटर का उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा ट्रेनिंग की विभिन्न जानकारियां विस्तृत रूप से लाभार्थियों को दी गई। तथा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेटलावद में वर्तमान में दो ट्रेड संचालित की जा रही है, जो पूर्णतःनिःशुल्क है। कोर्स की अवधि 6 माह की रहेगी एवं इसमें आठवीं उत्तीर्ण ड्रॉपआउट छात्र-छात्राओ ने प्रवेश लिया है। पूर्ण शाला छोड़ चुके छात्र-छात्राओं को ट्रेनरो के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी एवं ट्रेनिंग का समय शाला समय के आलावा शाम को 4 से 6 बजे के बीच रहेगा, जिसमें थ्योरि एव प्रैक्टिकल शामिल है।

मेघनगर बायपास पर विद्युत मण्डल की डीपी को जनहीत में हटाए जाने के निर्देश दिए

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा बुधवार को मेघनगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मेघनगर बायपास रेल्वे फाटक के समीप मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगाई गई डीपी को अन्यत्र लगाए जाने के निर्देश दिए। यहां पर आमजन द्वारा कलेक्टर महोदय को बताया कि यहां पर अंधामोड होने के कारण कभी भी जनहानी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए यहां से डीपी को हटाया जाए। कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार श्री रविन्द्र चौहान एवं विद्युत मण्डल के उपयंत्री को निर्देश दिए की तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

वाहनों की बैटरी चुराने वाले 2 तथा खरीदने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

खडे ट्रेक्टर, टेम्पो, डंपर, जेसीबी वाहनों की चुराते थे बैटरी, सोना खरीदने वाले आखिर क्यों पुलिस की पहुँच से बहार

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद थाना क्षेत्र की सारंगी पुलिस के हथे चैकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्ति ट्रेक्टर के पास मिलने पर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई जिन्होने अलग-अलग स्थानो से थाना पेटलावद के ग्राम करडावद, बावडी व चौकी सारंगी के ग्राम डाबडी, पालीवाल काम्पलेक्स के सामने सारंगी में खडे ट्रेक्टर, टेम्पो, डम्पर तथा जेसीबी की बेटरिया चोरी करना स्वीकार किया। उक्त व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हरिओम पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार निवासी बरवेट, रोहित पिता शान्तिलाल गुर्जर निवासी बाछीखेडा का होना बताया, पुलिस के अनुसार में आरोपियों ने पूछताछ अलग-अलग समय में पेटलावद के कबाडियों को बेटरी बेचना बताया आरोपियों की निशानदेही पर साजिद पिता रफीक मकरानी निवासी राजापुरा पेटलावद, युसुफ पिता मोहम्मद मंसुरी निवासी भगतसिंह मार्ग पेटलावद, शाहबाद पिता कुतुबुद्दीन शेख निवासी कैलाश मार्ग झाबुआ, शम्भु पिता जमनालाल निवासी पंथ बोराली, रवि पिता बुद्धीलाल निवासी पेटलावद को पकड़ा और उनसे खरीदी हुई बैटरियां भी जप्त की गई और कुल 06 अपराधों में धारा 379, 411 भादवि में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए गए जहॉ से सभी को जेल भेज दिया गया। मामले के पुलिस खुलासे के बाद चर्चा आम है कि पुलिस ने पिछली कई चोरियों के खुलासे कर चोरो से नगदी और जेवरात जप्त किये लेकिन पुलिस एक भी व्यापारी तक नही पहुँची जिन्होंने ने चोरी के जेवर खरीदे इस सबंध में थाना प्रभारी संजय रावत और चौकी प्रभारी अशोक बघेल से सवाल किए गए जिस पर उनका कहना है कि जल्द ही वो व्यापारी भी पुलिस की गिरफ्त होंगे पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है।

जप्त पोकलेन मशीन छोड़ने के मामले में सचिव पर कार्रवाई के निर्देश के बाद भी नही हुई कार्रवाई

मामला ग्राम पंचायत बामनिया में पहली बारिश में फूटे तालाब का

माही की गूंज, पेटलावद।

वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बामनिया में मनरेगा योजना में बने तालाब के पहली ही बारिश में फुटने के मामले में रोचक जानकारी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि, ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकारियों में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है। मामला ग्राम पंचायत बामनिया का है, जहाँ ग्राम पंचायत के काजलिया फलिये में सेमल वाली नाकी पर मनरेगा योजना का तालाब बना था जो कि बनने के बाद एक ही बारिश में फूट गया था। मामला दो वर्षो तक दबा रहा और फिर गाँव के ही यसवंत डामर के द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद ग्राम पंचायत द्वारा ताबड़तोड़ पोकलेंन मशीन से फूटे तालाब को सुधारने का कार्य शुरू किया। पोकलेन मशीन द्वारा चलाए जा रहे कार्य की शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुँच कर पोकलेन मशीन जप्त कर ग्राम पंचायत सचिव मुन्नालाल अरड के सुपर्द की थी, जो अगले ही दिन बिना किसी अधिकारी की जानकारी के मौके से चली गई।

एसडीएम और तहसीलदार दोनों ने दिया सचिव पर कार्रवाई करने का प्रतिवेदन, जिला पंचायत ने नही की कोई कार्रवाई

मामले की शिकायत के बाद पूरा प्रकरण जिला पंचायत सीओ के पास चल रहा है, जिसमे ग्राम पंचायत सरपंच, रोजगार सहायक, उपयंत्री और मनरेगा एसडीओ को नोटिस जारी किए गए। जांच में अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद द्वारा मौके पर जांच और मशीन जप्ती संबधी दस्तावेज भी भेजे गए, साथ ही मौके पर जप्त पोकलेन जो कि ग्राम पंचायत सचिव के सुपुर्द की गई थी, उसे बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी के छोड़ने पर ग्राम पंचायत सचिव पर लापरवाही बरतने के मामले में उचित कार्रवाई करने के पत्र एसडीएम और तहसीलदार द्वारा दिए गए थे। लेकिन आज दिनांक तक सचिव पर जिला पंचायत सीओ द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई। बताया जा रहा है जिम्मेदार अधिकारियों ने पूरा मामला लेन-देन कर दबा दिया, जिस कारण कोई कार्रवाई अब तक नही हुई।

शिकायतकर्ता यसवंत डामर ने बताया कि, जब मेरे द्वारा अब तक हुई कार्यवाही के प्रमाणित दस्तावेज निकाले गए तब ये जानकारी मिली जो कि गंभीर है कि, इतने बड़े अधिकारी द्वारा लिखित में सुपुर्द की मशीन को बिना किसी अधिकारी के जानकारी के न केवल छोड़ दिया गया, बल्कि उसी मशीन से कार्य को पूर्ण करवाया गया और अनुविभाग... और तहसील न्यायालय के दो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा लिखित में कार्रवाई करने का कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नही होना यही साबित करता है कि, कार्रवाई के नाम पर भ्रष्टाचार में सब अधिकारी डुबकी लगा रहे हैं।

रोजगार सहायक लटका मिला फांसी के फंदे पर

माही की गूंज, पारा।

पारा के समीप ग्राम फतेपुरा में धर्मशाला के पास एक युवक पेड़ पर लटका मिला। मामला सोमवार-मंगलवार रात के दरमियान का है। मामले की जानकारी तब हुई जब गाव वालो ने शुभ देखा कि, युवक का शव पेड़ पर लटक रहा था, तत्काल गाव वालो ने पुलिस को सूचना दी, मामला रानापुर थाने के अंतर्गत आता है। सूत्रों अनुसार जानकारी मिली कि, ग्राम छोटी सजवानी निवासी रमेश पुत्र नरवा मैड़ा (40) रस्सी के फहन्दे पर लटका मिला। रमेश ग्राम गोला छोटी मे रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत था। शव के पास एक बाईक खड़ी थी, पास ही पानी की बोतल व प्लास्टिक के चार ग्लास भी पड़े थें। रानापुर पुलिस ने मौका मुईना कर मामले को विवेचना मे ले लिया है, फिलहाल मौत का कारण पता नही चल पाया है।

जिमेदारो का क्या कहना

इस मामले की जानकरी रानापुर थाना प्रभारी से मो, 7049140528 मांगी तो जवाब मे कहा, मौत का कारण अभी पता नही चला है। मृतक का नाम पता पूछा गया तो प्रभारी ने जानकारी देने से पला झाड़ते हुए कह दिया 11 बजे जानकारी देदी जाएगी। 11 बजे दुबारा फोन लगाया तो थाना प्रभारी ने फोन नही उठाया।

गूंज असर...

क्षेत्र में रोड निर्माण में लगे ठेकेदारों को तहसील न्यायालय से नोटिस जारी

उपस्थित नहीं हुए ठेकेदार, सभी पर करेंगे कार्रवाई - तहसीलदार श्री वर्मा

माही की गूंज
दिया तले अंधेराः राजस्व सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण, ठेकेदार की मौज

13 जनवरी को प्रकाशित समाचार

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बिना राजस्व विभाग की अनुमति के सरकारी भूमि से हजारों मेट्रिक टन अवैध मोरंम और नदी का बंटा उठाकर सड़क के कार्य मे उपयोग लिया गया है। सूचना अधिकार में राजस्व विभाग से मिली चौकाने वाली जानकारी में खुलासा हुआ कि, बीते कई वर्षों से चल रहे विकास खण्ड में सड़क निर्माण के कार्य में लगे ठेकेदारों ने राजस्व विभाग से कोई अनुमति नहीं ली, न ही कोई आवेंदन किया। जिसके बाद गूंज द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाया था और राजस्व विभाग और खनिज विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए थे कि, आखिर हर हल्के में पटवारियों की उपस्थिति होने के बाद भी इतने बड़े स्तर पर शासकीय भूमि से बिना किसी अनुमति के कैसे अवैध उत्खनन् सम्भव है। सूचना अधिकार में मामला जानकारी में आने के बाद भी राजस्व विभाग में पूर्व तहसीलदार जितेंद्र अलावा द्वारा सड़क निर्माण में लगी एजेंसियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खबर के बाद जागा राजस्व विभाग, केवल एक ठेकेदार को दिया नोटिस, वो भी तारीख पर नहीं हुआ उपस्थित

गूंज द्वारा खबर प्रकाशित करने के बाद प्रभारी तहसीलदार जगदीश वर्मा ने मामले में कार्यवाही करते हुए जाँच के बाद करड़ावद-करवड़ मार्ग के ठेकेदार मानसिंह तोमर को कारण बताया सूचना पत्र जारी किया। हालांकि क्षेत्र में चार से पांच ठेकेदार बीते दो वर्ष से सड़क निर्माण करने में लगे हैं, लेकिन तहसील न्यायालय से सिर्फ एक ही ठेकेदार को 25 जनवरी को नोटिस देकर 27 जनवरी को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन जानकारी के अनुसार ठेकेदार की और से तहसील न्यायालय से दी गई तारीख पर कोई उपस्थित नहीं हुई। तहसीलदार जगदीश वर्मा का कहना है कि, जिन गांवों में कार्य चल रहा है या किया गया है, उन सभी की जांच कर सभी को नोटिस दिए जाएंगे। फिलहाल देहंदी मार्ग के ठेकेदार को नोटिस जारी किया है, जो अभी उपस्थित नही हुआ है, राजस्व विभाग द्वारा इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी।

खबर के बाद जागी पंचायत

बिना अनुमति निस्तार तालाब से पानी और मोरंम लेने वाले ठेकेदार को नोटिस

पंचनामा बनने के बाद राजस्व विभाग की ओर से नहीं हुई कोई कार्रवाई

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

आईटीआई परिसर बामनिया में करोड़ो की लागत से बन रहे नवीन कॉलेज भवन निर्माण में लगे ठेकेदार द्वारा आईटीआई के ठीक पीछे बने निस्तार तालाब से बिना अनुमति अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से बिना अनुमति मोटर पम्प से सीधे पानी लिया जा रहा था। दोनों ही कार्यो की जानकारी न तो ठेकेदार द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग को दी गई और मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। मामला गूंज के संज्ञान में आने के बाद प्रमुखता से मामले को उठाया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत की नींद खुली और अवैध रूप से बिना अनुमति के तालाब से मोरम और पानी लेने वाले ठेकेदार को ग्राम पंचायत ने नोटिस थमा कर नियमानुसार राशि ग्राम पंचायत में जमा करने को कहा गया है। हालांकि शिकायत और खबर के बाद भी ठेकेदार द्वारा रात के अंधेरे में काम जारी रखते हुए भवन के बेसमेंट का भराव कर उस पर सीमेंट कॉन्क्रीट कर दिया गया।

अवैध उत्खनन् की शिकायत पर पटवारी ने कार्रवाई की बजाए बन्द करवा दी मशीन

इन धाराओं में दिया नोटिस

आईटीआई परिसर में कार्य कर रहे ठेकेदार को ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम की धारा 9(ख), धारा-15 एवं धारा 23(ख) के अनुसार नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधान का कहना है कि, अगर ठेकेदार नियमानुसार राशि जमा नही करता और अनुमति से कार्य नही करता है तो प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्व विभाग की कार्रवाई का अब भी इंतज़ार

गूंज द्वारा मामला उठाने के बाद एसडीएम शिशिर गेमावत और तहसीलदार जगदीश वर्मा ने हल्का पटवारी को भेज कर पंचनामा बनवाया था, लेकिन दस दिन बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग की और से कोई कार्रवाई नही हुई है। वही ठेकेदार का इंजीनियर संदीप गारी ठेकेदार के प्रभावी होने और अधिकारीयो के नाम से गुमराह कर कार्य कर रहा है।

ट्राफिक जवान ना होने से आमजन हो रहे परेशान

माही की गूंज, थांदला।

नगर में बढ़ते वाहनों व अतिक्रमण के कारण आमजन परेशान है। वाहन चालक पार्किंग स्थल पर वाहन न रखकर बेवजह बीच रास्ते में वाहन खड़े कर अपनी शान समझते हैं। रास्ते परे खडे वाहनो की वजह से ट्राफिक जाम की स्थिती बन जाती है। नगर के नवीन बायपास थांदला-लिमडी मार्ग पर चौराहा होने से यातायात पुलिस या संकेतक नहीं होने से प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का लंबे समय से उक्त थाने में अभाव बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक को भी इस संदर्भ में जिम्मेदार नागरिकों ने अवगत करा कर दो ट्राफिक जवान की मांग की थी, किंतु पुलिस अधीक्षक द्वारा बल का अभाव होना बताया जा रहा है।

नगर के पिपली चौराहे पर स्थाई अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा यातायात बाधित होता है व घंटों जाम की स्थिति रहती है, चाय पीने व बाजार में खरिदारी करने वाले अपने वाहन कहीं भी बेतरतीब खड़ा कर घंटों गायब हो जाते है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस जवान की सख्त आवश्यकता है, किंतु पुलिस जवान व्यस्ततम चोराहों की बजाय शनि मंदिर, चेनपुरी रोड पर दिखाई देती है। विभाग के जिम्मेदार उक्त चौराहों पर दुर्घटना घटित होने के बाद भी नहीं जागा है, वही कुम्हार वाडा व आजाद चौक पर भी अतिक्रमण कर घूमटी धारक, हाथ ठेला गाड़ी रोड पर लगाकर व्यापार करने से व दुकानदारों के ग्राहकों के वाहन भी प्रतिदिन खड़े होने से यातायात बाधित होता है, जिससे राहगिरो को परेशानी का सामना करना होता है।

सूतरेटी चौराहे व लाख्याखाली पर पुलिस विभाग ने भारी वाहन के प्रवेश निषेध का बोर्ड भले लगा रखा है, किंतु नगर के नवीन बायपास मार्ग के प्रारंभ हो जाने के बाद भी भारी वाहन नगर में लंबे रास्ते पर जाने से बचने के लिए बाईपास से न जाते हुए नगर में घुस जाते हैं, जिससे भी नगर में जाम की स्थिति बनी रहती है। लिमडी बायपास मार्ग पर संकेतक व जवान नहीं होने से थाने के समीप वाली पुलिया पर दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार उक्त मार्ग पर दुर्घटना भी घटित हो चुकी है। विदित हो कि, झाबुआ-थांदला मार्ग पर प्रतिदिन ग्रामीण जन अपने रोजमर्रा के कार्य हेतु थांदला तहसील कार्यालय पहुंचते हैं, इस मार्ग पर स्थित शासकीय कार्यालय में उनका आना जाना लगा रहता है। पिछले दिनों एक बाईक सवार संकेतक न होने के कारण सिवा थाने से लगे नाले में जा गिरा, राहगिरो की सहायता से उसे व वाहन को बाहर निकाला गया।

मठ वाला कुआं और अस्पताल चौराहा पर भी चाय व बैंक के ग्राहाको की भीड़ लगी रहती है, जिससे दवाईयां लेने वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का भय लगा रहता है।

पिपली चौराहा पर खड़े बेतरतीब वाहन।

-थाने के पास नाले में गिरा बाईक सवार।

नगर के व्यापारी संचालक, गजेंद्र नायक गुमटी दिलीप सिसोदिया ने बताया कि, उक्त मार्ग पर ट्राफिक जवान, यातायात संकेतक न होने से प्रतिदिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राजु कटारिया का कहना है कि, नगर परिषद के सामने पड़ी पुराने अस्पताल की जगह को पार्किंग स्थल बना देना चाहिए, ताकि मरीजों और आमजन को आवागमन की समस्या न हो।

मोटर चालू करने गए युवक का शव नहर से हुआ बरामद

माही की गूंज, पेटलावद। किसानो के साथ कृषि कार्य करते समय हादसे और दुर्घटनाए होती ही रहती है, जिसमे कई बार किसान जान से भी हाथ धो बैठता हैं। पेटलावद क्षेत्र के ग्राम बावड़ी निवासी चंद्रपाल रामसिंह राठौर मंगलवार को खेत पर मोटर चालू करने गया जहॉ पांव फिसलने पर नहर में गिरने पर मौत हो गई। मंगलवार रात से नहर में ग्रामीण की चन्दपाल तलाश कर रहे थे, लेकिन सफलता नही मिली। आखिर नहर को रात में बंद करवाया गया तब कहीं जाकर बुधवार सुबह 10 बजे चंद्रपाल का शव बरामद हुआ है। फिलहाल चंद्रपाल की मौत को हादसा ही माना जा रहा है, पुलिस ने मौके पर पहुच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है।

अब तो अंखौड़ा उतार दो साहब, जिले में और भी बहुत कुछ है करने को

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई

कलेक्टर बंगले के बाहर लगे बेरिकेट्स अब बन गए है अघोषित पार्किंग।

एसपी बंगले के बाहर लगे इन बेरिकेट्स से वाहन चालकों को हो रही परेशानी।

पुलिस पेट्रोल पंप निर्माण करने में 3 फिट का नाला ही निगल गए साहब।

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई यह कहावत इन दिनों जिले व जिलाधिकारियों पर खूब ही सटीक साबित होती नजर आ रही है। जिले के अधिकारी चक्की के वो दो पाट है, जिसके बीच में जनता लगातार पिसती ही चली जा रही है। एक को टीकाकरण से फुरसत नही है तो दूसरे का ध्यान धंधे में है। दोनों ही जिलाधिकारियों ने मानों ''अंखौड़'' पहन रखा हो। जिससे उनका ध्यान इधर-उधर न भटके। शब्द ''अंखौड़ा'' वैसे तो प्रचलन में नहीं है, तो इसको विस्तार से कुछ यूं समझ लीजिए। ''घोड़े की आंखों का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है, इस वजह से जब तागे में चलते हुए या घुड़दौड़ आदि में उसका ध्यान इधर-उधर भटक जाता है और वो बिदक या पीछे रह जाता है। इसके समाधान के लिए घोड़े के दोनों आंखों के बाहर की तरफ चमड़े की पट्टी लगाई जाती है, जिसे इंग्लिस में हार्स ब्लाईंडर और हिंदी में ''अंखौड़ा'' कहा जाता है। ''अंखौड़ा'' लगाने के बाद घोड़े का दृष्टि क्षेत्र 30 डिग्री तक ही सीमित हो जाता है और इससे वो सिर्फ सामने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखता है।'' कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों जिले में जमे कलेक्टर और एसपी का है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने टीकाकरण को लेकर तो पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने इन दिनों कानून व्यवस्था की बजाय धंधे में ध्यान देने का ''अंखौड़ा'' पहन रखा है।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा को इन दिनों एक भूत सवार है टीकाकरण का, इसके अलावा इन्हे जिले में और कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि जिले में सिर्फ टीकाकरण ही इनकी एक जिम्मेदारी बची है। हालांकि प्रशासनिक हवाले से जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। बावजूद इसके साहब की आंखों से ''अंखौड़ा'' नहीं उतर रहा है। मगर भोपाल से जारी कोरोना गाइडलाइन की जिले में स्थिति ''ढाक के तीन पात'' ही साबित हो रही है। कोरोना गाइड लाइन को लेकर प्रशासन भी मैदान से ऐसे गायब ''मानो गधे के सिर से सिंग।'' ना कोई चालानी, ना कोई सख्ती। हां अपनी शेखी बघारने के लिए कलेक्टर और एसपी साहब ने एकाध बार नगर भ्रमण पर निकलकर किसी बस के कंडेक्टर का चालान जरूर काट दिया। इसके बाद शायद आगे कोई कार्रवाई हुई ही नहीं...? मतलब ''आगे-आगे पाट और पीछे सपाट।

क्या तमगे के लिए पहना है अंखौड़ा?

वैसे तो कलेक्टर को उस घोड़े की तरह होना चाहिए था जिसकी दृष्टि 180 डिग्री तक होती है। मगर साहब ने अपनी आंखों पर ''अंखौड़ा'' लगा लिया। इस ''अंखौड़े'' का असर यह हुआ कि, साहब की दृष्टि भी तांगे या घुड़दौड़ के उस घोड़े जैसी हो गई जो सिर्फ 30 डिग्री तक ही देख पाता है। मतलब उसका ध्यान सिर्फ एक ही दीशा में रहता है। कलेक्टर साहब भी इन दिनों सिर्फ एक ही दीशा में काम कर रहे है। उन्हे जिले में हो रही हलचल मानों दिखाई ही नहीं दे रही हो। क्या जिले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कोई दूसरा विभाग नहीं है, जिसे देखने की जरूरत हो या जिले की जनता को टीकाकरण के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नही है। जो टीकाकरण का काम कलेक्टर मिश्रा कर रहे है कहीं वह जनता के हित को साधते हुए अपना तमगा बढ़ाने का तो नहीं है? क्योंकि कलेक्टर साहब की कार्यशैली तो यही दर्शाती है। क्या वाकई यह अंखौड़ा साहब को तमगा दिला पाएगा...?

बंगलों के आगे बेरिकेट्स लगवाने का क्या मतलब?

जिला मुख्यालय की ही बात करें तो शहर में कई ऐसे मुद्दे है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। शहर की मुख्य सड़क जिसे उत्कृष्ट सड़क का नाम दिया गया है, बदहाल स्थिति में है। समझ ही नहीं आ रहा है कि सड़क पर गड्ढे है या गड्ढों पर सड़क जबकि जिले के दोनों ही आला अधिकारियों के बंगले इसी सड़क पर है। दोनों ही अधिकारियों ने ''अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता'' कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने बंगलों के आगे बेरिकेटिंग करवा रखी है। इस बेरिकेटिंग का उद्देश्य क्या है यह आमजन को अब तक समझ नहीं आ पा रहा है। मगर बुद्धीजीवियों का मानना है कि, यह बेरिकेटिंग साहब के बंगलों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। मतलब खराब सड़क को सुधरवाने की बजाय साहब लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खस्ताहाल सड़क पर बेरिकेटिंग करवा दी। इस बेतुकी बेरिकेटिंग से साहब लोगों की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन आमजन के लिए यह खस्ताहाल सड़क पर एक और दंश जैसा साबित हो रही है। पहले तो सड़क खराब, उस पर साहब के बंगलों के बाहर रखे यह बेरिकेट्स आमजनता को तकलीफ ही पहुंचा रहे है। कलेक्टर बंगले के पास लगे बेरिकेट्स की आड़ में साहब के बंगले में काम करने या आने-जाने वालों के लिए अघोषित पार्किंग बन चुकी है। कलेक्टर बंगले के बाहर सार्वजनिक सड़क पर लगे यह बेरिकेट्स और अघोषित पार्किंग दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहे है। एसपी बंगले के समीप अभी हाल ही में इस खस्ताहाल सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, बावजूद इसके वहां साहब की सुरक्षा के लिए रखे गए बेरिकेट्स हटाए नहीं गए। यह सीधे तौर पर आमजन के गले नख देने वाला ही लग रहा है। शहर की उत्कृष्ट खस्ताहाल सड़क पता नहीं कब सही होगी मगर कलेक्टर सहित कई जिला अधिकारियों के बंगलों में आए दिन लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण के काम किए जा रहे है। कुछेक महीने पहले कलेक्टर बंगले के अंदर डामरीकरण का कार्य हुआ। उसके बाद कुछेक दिन पहले जिला जनपद सीईओ के बंगले में भी डामरीकरण का कार्य किया गया। यह बात और है कि, विधानसभा में यह मुद्दा उठ चुका है कि, कुछ जिलों में कलेक्टरों व जिलाधिकारियों के बंगलों पर 100 करोड़ से अधिक रूपए लोक निर्माण विभाग ने फूंक दिए, जिसमें झाबुआ जिले का नाम भी शामिल है। यहां यह समझ नहीं आता कि, इन अधिकारियों के बंगलों में ऐसा किस तरह का आवागमन होता है कि, हर साल बंगालों की सड़कें नई बनानी पड़ जाती है...? जबकि आमजनता तो एक बार सड़क बनने के बाद कम से कम एक दशक तो रोते-गाते निकाल ही लेती है। हाय रे जिले की बदनसीबी...? आसपास के जिलों में कलेक्टरों के तबादले पर तबादले हो रहे है और यहां साहब अंगद के पैर की तरह जमे हुए है।

और भी है मुद्दे

इसके अलावा भी जिला मुख्यालय होने के चलते शहर के कई मुद्दे है। नगर के तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर बात इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है कि, सालों बीत गए लेकिन अब तक शहर के तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू ही बहा रहे है। नगर पालिका इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी साबित हुई है। ओर तो ओर जिला इस वर्ष गरीबी के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहली और दूसरी लहर से कई गुना अधिक पिछले 28 दिनों में मामले लगभग 1700 के पार। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाई गई गाइडलाईन प्रशासनिक नपुंसकता की वजह से हवा-हवाई दिखाई दे रही है। ऐसे कई अनछुए मुद्दे है, जिन पर काम करने की जरूरत है। तो साहब अपना ''अंखौड़ा'' उतारिए और काम कीजिए।

क्या इनका है धंधे में ध्यान

जिले में कानून व्यवस्था भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। पुलिस महकमा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। नशेड़ी पुलिस वाले आए दिन अखबारों की सुर्खियों में होते है। जिले में चोरी, लूट, डकैती, हत्या, नशाखोरी मानों प्रचलन सी होती जा रही है। मगर जिले का कुशल पुलिस महकमा ऐसा कि, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सर, करते हुए मामलों को सुलझा ही लेता है। रेकार्ड की सफाई और साहब लोगों के तमगों के चक्कर में कभी-कभी साहब की टोपी अधिनस्तों के सिर पर आ जाती और इस टोपी को उतारने के चक्कर में अधिनस्तों की अपनी जेबें खाली हो जाती और यह सब काम गुप्ता जी के राज में गुप्त तरीके से हो जाते। कुशलता इतनी कि, गुप्ता जी - गुप्ता जी से, गुप्त तरीके से झाबुआ कोतवाली को गुप्तदान करवाते हुए आईएसओ सर्टिफाइड करवा लिया।

वैसे गुप्ता जी का ''अंखौड़ा'' थोड़ा चौडा है, क्योंकि वे अपने महकमें की पर्दापोशी के साथ धंधे में भी ध्यान दे रहे है। पिछले कुछ समय में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने अपने विभागीय कर्मचारियों को कुछ ज्यादा ही सौगाते दी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आर्मी की तर्ज पर पुलिस कैंटीन का शुभारंभ आईजी द्वारा किया गया। जहां पुलिसकर्मियों को सस्ता सामान मिलेगा और विभाग का आर्थिक लाभ। इसके अलावा जल्द ही पुलिस पेट्रोल पंप का भी शुभारंभ होना है, लेकिन पेट्रोल पंप निर्माण में नाले पर अतिक्रमण कर उसे बंद करना तो कोई अच्छी बात नहीं।

पेट्रोल पंप निर्माण में नाले को कर दिया बंद

पुलिस पेट्रोल पंप की जो सौगात पुलिस अधीक्षक देने जा रहे है, उसके निर्माण में पीछे से गुजर रहे एक 3 फीट के नाले को उस पर निर्माण कर बंद कर दिया गया है। जबकि कई सरकारी आवासों का ड्रेनेज इस नाले से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सिंचाई कॉलोनी व दूसरी तरफ खुद पुलिस विभाग के आवासों का ड्रेनेज इस नाले से होकर गुजरता है। मगर पुलिस विभाग के पेट्रोल पंप बनने से यह नाला पूरी तरह से बंद हो चुका है। राजगढ़ नाके के बगीचे के पीछे से लेकर डीआरपी लाइन चौराहे तक जाने वाले इस नाले के बंद हो जाने से बारिश के दिनों में नाले की सारी गंदगी सिंचाई कॉलोनी में फैलेगी। अब इन सरकारी आवासों का ड्रेनेज कैसे और कहां जाएगा यह तो गुप्ता जी ही बता सकते है। वैसे इस नाले के आसपास सबसे ज्यादा गंदगी पुलिस विभाग के ही लोग फैलाते है। हालांकि इस पेट्रोल पंप से पुलिस विभाग को बहुत अधिक आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि साहब के सर बंधा ''अंखौड़ा'' अभी इसी तरफ है, यानि धंधे में ध्यान। जिले में कानून व्यवस्था सही चले ना चले धंधा अच्छा चलना चाहिए और आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों जिला अधिकारियों की नियति कुछ ऐसी हो गई है कि, ''अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता''।

संपादकीय

चुनावी मौसम में पेपरलेस बजट

जब संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट पेश किया तो कई मायनों में यह अलग था। कई परंपराएं बदलीं, ये पेपरलेस बजट और भाषण संक्षिप्त था। पांच राज्यों के चुनाव के बीच आए बजट में भले ही नए करों का

प्रावधान नहीं था, लेकिन यह लोकलुभावन बजट भी नहीं था। वर्ष 2022-23 के बजट में नौकरीपेशा वर्ग को आयकर में छूट न मिलने पर निराशा जरूर हुई, जो कोरोना संकट में आय संकुचन के दौर में राहत की उम्मीद लगाये हुए था। दरअसल, सरकार का पूरा ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी दूर करने को बड़ी पहल होती नजर नहीं आई।

सरकार का कहना है कि, अमृतकाल में देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई है। इसके अलावा भारत में दखल बनाती क्रिप्टो करंसी पर तीस फीसदी टैक्स लगाने, इसके लेन-देन में टीडीएस लगाने, आरबीआई द्वारा इस वर्ष डिजिटल करंसी जारी करने, डाकघरों को मुख्य बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, ई-पासपोर्ट सेवा आरंभ करने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में की गई। वहीं पूर्वोत्तर के विकास हेतु एक हजार 500 करोड़ रुपए आवंटित करने तथा आगामी तीन वर्षो में चार सौ वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई। सरकार ने अर्थव्यवस्था में गति लाने के क्रम में राजस्व घाटा 6.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है तथा वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपए रहने का आकलन है।

वहीं विपक्ष कह रहा है कि, देश में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कोरोना संकट से जूझते आम आदमी को यह बजट राहत नहीं देता। यह भी कि एक ओर सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा तथा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं नदी जोड़ योजना के जरिए पारिस्थितिकीय संतुलन से खिलवाड़ कर रही है।

दरअसल, लगातार दो वर्ष से महामारी का दंश झेल रहे और आय के स्रोतों के संकुचन से त्रस्त लोग आस लगाए बैठे थे कि सरकार की तरफ से उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने की दिशा में पहल होगी। मगर सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को ही प्राथमिकता दी है। लेकिन आपूर्ति बढ़ाना तभी सार्थक होगा, जब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी। वह भी उन वैश्विक रिपोर्टों के बीच कि कोरोना संकट में देश के अस्सी फीसदी लोगों की आय में संकुचन हुआ है और अमीर लोगों की आय दुगुनी से अधिक हो गई है। वहीं लंबे किसान आंदोलन के बाद उम्मीद थी कि, सरकार किसानों को राहत देने के लिए कुछ बड़ा करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा था। कुछ लोग देश की आधी आबादी को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की उम्मीद कर रहे थे।

नि:संदेह कोरोना संकट में कृषि क्षेत्र ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल दिया था। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि की उम्मीद भी जताई जा रही थी। हालांकि, बजट में किसान ड्रोन, प्राकृतिक खेती, लैंड डिजिटाइजेशन, एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रखने, नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप्स के वित्तीय पोषण, एक हजार 208 मीट्रिक टन धान-गेहूं की खरीद के प्रावधान रखने से किसानों को राहत देने की पहल जरूर हुई है।

दूसरी ओर वक्त की जरूरत के हिसाब से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही व्यावसयिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय हुआ है। अगले पांच वर्ष के लिए छह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बताता है कि, एमएसएमई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दो लाख आंगनवाड़ी अपग्रेड करने का मकसद कुपोषण व अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का प्रयास है। लेकिन हेल्थ सेक्टर में महामारी के दौर में अपेक्षित बजट वृद्धि की कमी खलती है। इसके बावजूद 60 लाख रोजगारों का सृजन, 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य, डाकघरों में एटीएम, पीएम ई-विद्या टीवी चैनल बढ़ाने तथा 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को ही दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देने वाला बजट

जयंतीलाल भंडारी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2022-23 का बजट कोरोना की चुनौतियों से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील करने और विभिन्न वर्गों की मुश्किलों को कम करने के लिए एक अभूतपूर्व बजट है। आगामी बजट के तहत कृषि और किसान हितों, बुनियादी ढांचे की मजबूती, उद्योग-कारोबार की गतिशीलता, निर्यात वृद्धि, शेयर बाजार को प्रोत्साहन, रोजगार के नए अवसर, महंगाई पर नियंत्रण, नई मांग का निर्माण, टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लिए भी प्रभावी प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। वित्तमंत्री सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन की बूस्टर डोज देते समय राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) को जीडीपी के 6.4 फीसदी तक विस्तारित करने में कोई संकोच नहीं किया है। इस बजट से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि, इस वर्ष 2022-23 का बजट बनाते हुए वित्तमंत्री के समक्ष कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, आय की असमानता, करीब 8 फीसदी की बेरोजगारी दर, सरकारी विभागों की कमजोर व्यय क्षमता ,निजीकरण पर कम सफलताएं जैसी विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुश्किलें मुंह बाए खड़ी थीं।

निःसंदेह नए बजट में खेती और किसानों के हितों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि की विकास दर बढ़ाने और छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि सुधारों को व्यापक प्रोत्साहन दिया गया है। नए बजट में प्राकृतिक खेती और मांग आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घोषणा की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाने वाली सरकारी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की गैर-कृषि आय बढ़ाने के लिए पशुधन विकास, डेरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन के साथ किसानों को आधुनिक तकनीक मुहैया करने के लिए नयी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कृषि क्षेत्र में कुशल मानव संसाधनों की जरूरत के मद्देनजर कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित किया गया है एवं कृषि अनुसंधान पर आवंटन बढ़ाया गया है। ऊंचे दाम वाली विविध फसलों के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन और छोटे किसानों की आमदनी में वृद्धि जैसे कदमों की घोषणा भी नए बजट में की गई है।

आगामी बजट में वित्तमंत्री ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों, खपत और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई है वर्ष 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 2.9 फीसदी है। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

चूंकि सरकार चाहती है कि, आने वाले वर्षों में दुनियाभर में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे, ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में वित्तमंत्री ने नए बजट में बड़े ऐलान किए हैं। नए बजट में वित्तमंत्री रिकॉर्ड निर्यात का लक्ष्य रखते हुए विभिन्न कच्चे मालों पर आयात शुल्क घटाते हुए दिखाई दी हैं। ये आयात शुल्क खासतौर से ऐसी चीजों के कच्चे माल पर घटाए गए हैं, जिनका पीएलआई क्षेत्र के उद्योगों में उपयोग होता है। नए बजट में वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के कदम भी दिखाई दे रहे हैं।

नए बजट के तहत वित्तमंत्री ने देश में खुदरा कारोबार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने और कारोबार करने के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या घटाकर उनका अनुपालन बोझ हल्का करने के तरीके भी सुनिश्चित किए हैं। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाई गई है। साथ ही एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नए बजट में विशेष घोषणा की गई है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। गारंटी कवर को 5 लाख करोड़ रुपये तक विस्तारित किया गया है।

नए बजट में आतिथ्य, पर्यटन, आराम और अन्य संपर्क वाली सेवाओं को समर्थन दिया गया है। नए बजट में नई शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास, डिजिटल विकास, पीएमई-विद्या का विस्तार किया गया है। शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के साथ-साथ रोजगार वृद्धि के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को भारी प्रोत्साहन दिए गए हैं। नए बजट में शोध एवं नवाचार, निर्यात डेवलपमेंट फंड तथा फार्मा उद्योग आदि के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे व टीकाकरण के लिए अधिक निवेश किया गया है। नए बजट में डिजिटल करंसी लाए जाने का ऐलान किया गया है।

नए बजट में सामाजिक क्षेत्र पर आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति के साथ-साथ गरीबों और अन्य वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं आती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगनवाड़ी और पोषण-2 को नया रूप दिया गया है।

नए बजट की एक बड़ी कमी छोटे करदाताओं व मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाने हेतु सरकार के द्वारा राहत के प्रावधान न होना है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। देश के शेयर बाजार को आगामी बजट से तेजी से बढ़ने के प्रोत्साहन दिए गए हैं। यही कारण है कि जैसे-जैसे वित्तमंत्री बजट प्रस्तुत करती गईं वैसे-वैसे शेयर बाजार ऊंचाई पर पहुंचता गया। लेकिन वित्तवर्ष 2022-23 के बजट के समक्ष कई चुनौतियां भी उभरकर दिखाई दे रही हैं। नया बजट बनाते समय वृद्धि अनुमान कच्चे तेल की 70-75 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर आधारित हैं। जबकि इस समय कच्चे तेल की कीमतें करीब 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं।

हम उम्मीद करें कि, नए बजट से एक ओर आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, नई मांग का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक विकास दर करीब 9 फीसदी के स्तर पर पहुंचते हुए दुनिया में अव्वल दिखाई दे सकेगी। हम उम्मीद करें कि नया बजट कोरोना की चुनौतियों के बाद अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देने वाला एक महत्वपूर्ण बजट सिद्ध होगा।

चुनावी घोषणाओं से भरा बजट

सिद्धार्थ शंकर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए बजट में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। बजट में सभी तबके के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें किसानों को डिजिटल सेवा देना, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाना शामिल है। इसके अलावा पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, 12 करोड़ से अधिक किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है। पीएम किसान के 12 करोड़ से अधिक किसानों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में पीएम किसान की राशि कम से कम डेढ़ गुनी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सका। नौकरी-पेशा करने वाले लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है। सीतारमण ने बजट 2022 में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। इससे इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद लगाए हुए आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की और न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है। बावजूद इसके बाजार ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। बजट भाषण के दौरान बैंकिंग स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स करीब 750 अंक मजबूत होकर 58,780 अंक के पार कारोबार कर रहा था। बजट पर सरकार ने किसानों पर खास जोर दिया है। किसान आंदोलन के नुकसान से निपटने सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। किसानों को डिजिटल सेवा देने, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने, देशभर में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के ऐलान किए गए हैं। वर्ष 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। पिछले वर्ष मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बात की थी। अब बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44 हजार 605 करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए बजट से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि सरकार के इस बजट में चुनावी राज्यों के लोगों के लिए सौगात होने की संभावना है। खासकर उन किसानों के लिए जो तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक साल से ज्यादा वर्षों तक चले किसानों आंदोलन से सरकार पहले ही बैकफुट में है। ऐसे में सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का पिटारा खोला है। किसानों के साथ ही आम लोगों को भी सरकार ने राहत दी है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 80 लाख नए आवास पूरे किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था। लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। कुल मिलाकर बजट को सर्वहितैषी माना जा सकता है। इसका असर क्या होगा, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।

आर्थिकी के अहम मुद्दों की अनदेखी

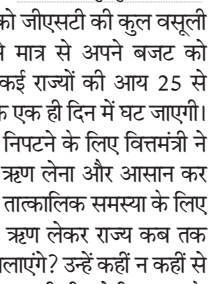

भरत झुनझुनवाला

आर्थिकी के अहम मुद्दों की अनदेखी

वित्तमंत्री ने बजट में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कई मशीनों पर आयात कर बढ़ाया है, जिनका भारत में उत्पादन हो सकता था। इससे भारत में मशीनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मोबाइल फोन के लेंस के आयात पर छूट दी गई है। केमिकल में भी जहां देश में उत्पादन क्षमता उपलब्ध है वहां आयात करों को बढ़ाया गया है। सोलर बिजली के उत्पादन के लिए घरेलू सोलर पैनल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में कुल बजट का पिछले साल 58 प्रतिशत घरेलू स्रोतों से खरीद की जा रही थी जो इस वर्ष बढ़ाकर 68 प्रतिशत कर दिया गया है। यह सभी कदम सही दिशा में हैं। इनसे घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया बढ़ेगा।

लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था पुनः चल निकलेगी इस पर संशय है। मुख्य कारण यह है कि, सरकार सप्लाई बढ़ाने की अपनी पुरानी गलत नीति पर ही चल रही है। जैसे घरेलू उत्पादन को 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' यानी उत्पादन के अनुसार उन्हें सहयोग मात्रा दिए जाने को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि, जब बाजार में मांग नहीं है तो उद्यमी उत्पादन करेगा क्यों और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' लेने की स्थिति में पहुंचेगा कैसे? उद्यमी के लिए प्रमुख बात होती है कि वह अपने माल को बाजार में बेच सके। जब तक देश के नागरिकों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी और वे बाजार में माल खरीदने को नहीं उतरेंगे तब तक बाजार में मांग उत्पन्न नहीं होगी और घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जैसे यदि किसी की जेब में नोट न हो तो बाजार में आलू 20 रुपये के स्थान पर 10 रुपये प्रति किलो में भी उपलब्ध हो तो वह खरीदता नहीं है। इसी प्रकार 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' की उपयोगिता तब है जब बाजार में मांग हो। लेकिन वित्तमंत्री ने आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। करना यह चाहिए था कि सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव को खत्म करके आम आदमी को सीधे नगद वितरण करना चाहिए, जिससे कि आम आदमी बाजार से माल खरीद सके और अर्थव्यवस्था चल सके। जो रकम 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' में दी जा रही है उसे सीधे जनता के हाथ में वितरित करना चाहिए, जिससे वित्तमंत्री चूक गईं।

वित्तमंत्री ने कहा है कि, सरकारी निवेश में वृद्धि की गई है। यह भी सही है लेकिन बड़ा सच यह है कि, सरकार के कुल बजट में 5 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमे पूंजी खर्चों में 2 लाख करोड़ की और सरकारी खपत में 3 लाख करोड़ की। कहा जा सकता है कि यह 2 लाख करोड़ की वृद्धि अच्छी है और है भी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस समय जब देश आयातों से हर तरफ से पिट रहा है, उस स्थिति में अपने देश में बुनियादी संरचना एवं अन्य पूंजी खर्चों में भारी वृद्धि करने की जरूरत थी, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े हो सकें। उस जरूरत को देखते हुए सरकारी खपत में 3 करोड़ की वृद्धि और सरकारी निवेश में 2 करोड़ की वृद्धि उचित नहीं दिखती है। अधिक वृद्धि पूंजी खर्चों में की जानी चाहिए थी जो कि वित्तमंत्री ने नहीं की है। इसलिए हम विश्व अर्थव्यवस्था में वर्तमान की तरह पिटते रहेंगे

ऐसी संभावना है। सरकारी कर्मियों के लिए एसयूवी खरीदने से हम विश्व बाजार में खड़े नहीं होंगे।

वित्तमंत्री ने जीएसटी की वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि की बात कही है जो कि सही भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि, यदि जीएसटी में पिछले समय की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; तो जीडीपी में मात्र 9 प्रतिशत की वृद्धि क्यों? कारण यह है कि जो 9 प्रतिशत की वृद्धि बताई जा रही है यह विवादास्पद है। जीडीपी की गणना अपने देश में मुख्यतः संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जीएसटी में वृद्धि उत्पादन के कारण नहीं बल्कि इसलिए हो रही है कि असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, असंगठित क्षेत्र का उत्पादन घट रहा है और वह उत्पादन जो अभी तक असंगठित क्षेत्र में होता था वह अब संगठित क्षेत्र में होने लगा है। जैसे बस स्टैंड पर पहले रेहड़ी पर लोग चना बेचते थे और अब पैकेट में बंद चना बिक रहा है। असंगठित रेहड़ी वाले का धंधा कम हो गया और उतना ही उत्पादन संगठित पैकेटबंद चने का बढ़ गया। कुल उत्पादन उतना ही रहा। लेकिन जीएसटी रेहड़ी वाला नहीं देता था और पैकेटबंद उत्पादक जीएसटी देता है इसलिए जीएसटी की वसूली बढ़ गई। वित्तमंत्री को जीएसटी की वृद्धि को गंभीरता से समझना चाहिए कि इसके समानांतर जीडीपी में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? मेरे अनुसार यह एक खतरे की घंटी है कि छोटे आदमी का धंधा कम हो रहा है, उसकी क्रय शक्ति कम हो रही है और देश का कुल उत्पादन सपाट है जबकि जीएसटी बढ़ रही है।

जीएसटी की वसूली का दूसरा पक्ष राज्यों की स्वायत्तता का है। जून, 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों द्वारा जीएसटी में जो वसूली की कमी हुई है, उसकी भरपाई करना बंद हो जाएगा। जुलाई, 2022 के बाद राज्यों को जीएसटी की कुल वसूली में अपने हिस्से मात्र से अपने बजट को चलाना होगा। कई राज्यों की आय 25 से 40 फीसदी तक एक ही दिन में घट जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए वित्तमंत्री ने राज्यों के लिए ऋण लेना और आसान कर लिया है जो कि तात्कालिक समस्या के लिए ठीक है लेकिन ऋण लेकर राज्य कब तक अपना बजट चलाएंगे? उन्हें कहीं न कहीं से आय तो अर्जित करनी ही पड़ेगी। आज के संकट को 5 साल बाद पीछे धकेल देने से संकट समाप्त नहीं होता है। इसी संकट को जीएसटी को लागू करते समय 5 वर्ष के लिए पीछे धकेला गया था और अब इसे और पीछे धकेला जा रहा है। वित्तमंत्री को जीएसटी में लचीलापन लाना चाहिए और राज्यों को अपने विवेक के अनुसार अपने राज्य की सरहद में बिकने वाले माल पर जीएसटी की दर में परिवर्तन करने की छूट देनी चाहिए। इस बजट का एकमात्र गुण मेक इन इंडिया के तहत विशेष वस्तुओं के आयात कर में वृद्धि करना है। बाकी अर्थव्यवस्था की सभी मूल समस्याओं की अनदेखी की गई है।

कोरोना की तीसरी लहर में बाजार से गायब जागरूकता

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

कोरोना की तीसरी लहर में अब तक जिले में कुल 515 मरीज मिल चुके हैं। जिला अस्पताल में अभी केवल एक मरीज भर्ती हैं। बाकी 321 घर पर ही उपचार ले रहे हैं। शहर में कोरोना का संक्रमण दबे पांव बढ़ रहा है। इसकी पुष्टि अब तीन दिन में मिले 327 मरीज कर रहे हैं। शुक्रवार से सैंपल भोपाल की निजी लैब में भेजना शुरू हुए है और शनिवार को ही सबसे पहले आई रिपोर्ट में 98 मरीज मिले थे। इसके बाद रविवार को मिली रिपोर्ट में 117 मरीज मिले हैं और अब सोमवार को 131 मरीज पाजीटिव मिले हैं। हालांकि यह भी सही है कि, अभी तक महज 23 लोग जिला अस्पताल में भर्ती किए गए है और इनमें से 22 की छुट्टी भी हो चुकी है। बाकी बचे एक मरीज भी स्वस्थ हैं। सोमवार को भी एक हजार सैंपल की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 888 सैंपल की जांच भोपाल की निजी लैब व मंदसौर की दो निजी लैब में हुई है। इसके अलावा 113 लोगों की रेपिड टेस्ट हुई है।

बाजार से गायब जागरुकता

तीसरी लहर के आगमन के बाद से लगातार हर प्रचार तंत्र से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। इसके बाद भी शहर सहित जिले भर में भीड़ भरे क्षेत्रों में व बाजारों में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। दो गज की दूरी का पालन भी नहीं कर रहे हैं। पहले विधायक यशपालसिंह सिसौदिया, कलेक्टर गौतमसिंह व एसपी सुनील कुमार पांडेय बाजारों में घूमकर लोगों को मास्क पहना चुके हैं। लगातार अपील भी की जा रही है कि, कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय करें। जिले में कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण व अन्य उपाय भी कर रहा है। दोनों डोज लगने के बाद कोरोना संक्रमण का डर कम हो रहा है पर लोग बिलकुल लापरवाह हो गए हैं, अधिकांश ने मास्क पहनना बिलकुल ही छोड़ दिया है। थोड़ी-थोड़ी देर में सैनिटाइजर का उपयोग या साबुन से हाथ धोने का उपाय नहीं हो रहा है। भीड़-भाड़ वाले बाजारों के साथ ही बस, ट्रेन या सार्वजनिक परिवहन में आते-जाते समय भी लोग मास्क का बिलकुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं।

आ सकते हैं ओमिक्रान वैरिएंट की चपेट में

विशेषज्ञ अभी भी लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि, कोरोना के ओमिक्रान वैरिएंट की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। कोविड-19 के ओमिक्रान वैरिएंट ने लोगों में एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नया वैरिएंट वायरस के व्यवहार को ही बदल रहा है। इससे चिंताएं भी बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि, यह नया संस्करण डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंदौर में भी नए वैरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह बहुत घातक है। टेक्नीकल एडवायजरी ग्रुप इस नए वैरिएंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ताकि संक्रमण की गंभीरता का पता लगाया जा सके।

ओमिक्रान के लक्षण

ओमिक्रान के प्रमुख लक्षणों में जरुरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी शामिल है। कुछ मामलों में ही हल्का तेज बुखार भी हो सकता है। मरीज अस्पताल में भर्ती होने की जरुरत के बिना पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम है। मरीज के लक्षण डेल्टा वैरिएंट से काफी अलग हैं। वैरिएंट 40 वर्ष या उससे कम उम्र वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि अभी तक जिन लोगों में ओमिक्रान के लक्षण दिख रहे हैं उनमें से लगभग आधे रोगियों का टीकाकरण नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा लोग एक से दो दिन तक गंभीर थकान की शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सिरदर्द और शरीर में दर्द भी महसूस हो रहा है।

वैक्सीन ही है बचाव

विशेषज्ञ अब भी कोविड-19 के नए ओमिक्रान वैरिएंट से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि, नए स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी अब भी जरूरी है इसके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने रहें। भीड़-भाड़ वाली सामूहिक जगहों पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा नियमित रुप से हाथों और सतहों को धोने की अब भी जरूरत है। विशेषज्ञ टीकाकरण होने के बाद भी इसके लक्षणों को पहचानने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

पुत्र से परेशान पिता ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की पिपलोदा तहसील में एक अजीब ओ गरीब मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने पुत्र से परेशान होकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। ग्राम बडायला माताजी तहसील पिपलौदा निवासी मांगीलाल बागरी ने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखते हुए बताया कि, वो एक अंत्यत गरीब तथा वयोवृद्ध किसान है और कृषि भूमि सर्वे के 1320 रकबा 0.40 हेक्टेयर भुमि ग्राग बडायला में स्थित है, तथा मेरे 3 पुत्र जगदीश, रामप्रसाद और भरत है। मांगीलाल का कहना है कि, मेरे द्वारा बाजार से कर्ज लेकर मेरे तीनो पुत्रो के विवाह व अन्य कार्यक्रम आदी करवाए तथा सभी पुत्रो को रहने हेतु मकान में हिस्सा भी दे दिया है। अब मुझ प्रार्थी को मेरा बाजार कर्ज अदा करना है, जिसको अदा करने के लिए मै मेरी उपरोक्त भुमि पर कृषि कार्य कर मेहनत से व स्वाभीमान से अपना कर्ज अदा करना चाहता हुँ। किन्तु मेरा मंझला पुत्र रामप्रसाद मुझसे आए दिन विवाद कर जमीन मांगता है, मैं यदि उसको जमीन दे दूंगा तो अपना कर्ज कैसे अदा करूंगा। इस संबंध में पुलिस थाना पिपलौदा व तहसील कार्यालय पिपलौदा में आवेदन प्रस्तुत कर सहायता चाही गई थी, किन्तु पिपलौदा पुलिस द्वारा उल्टा मेरे ही खिलाफ 3-3 बार 151 में कायमी कर दी गई। तहसीलदार द्वारा भी मुझे सहयोग नही किया जा रहा है, मैने मेरी भुमि में फसल बोई है, किन्तु मेरा पुत्र रामप्रसाद और उसकी पत्नी मुझे भुमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे रहें है, सिंचाई नहीं करने दे रहें है जिससे मुझ गरीब की फसले खराब हो रही है और मुझे आर्थीक नुकसान हो रहा है, जिस कारण मैं काफी परेशान और प्रताडीत हो रहा हैं। इस कारण मै ईच्छा मृत्यु की अनुमति चाहता हूँ और श्रीमान से निवेदन करता हूँ कि, मुझे आज दिनांक से 1 माह में ईच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कि जाने और यदि 1 माह में भी अनुमति नहीं दी जाती है तो मै इसको स्वतः ही आपकी अनुमति मान लूंगा।

नवागत कप्तान ने चार्ज लेने के बाद मीडिया से की चर्चा, जारी रहेगी बदमाशों के विरुद्ध मुहिम

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के नए कप्तान अभिषेक तिवारी ने रतलाम में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा की। माफिया अभियान, यातायात समस्या, अपराधों पर नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर नए एसपी ने खुलकर अपनी बात रखी। नवागत एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि, मुख्य पुलिसिंग हमेशा फील्ड पर रहने वाले आरक्षक को करनी पड़ती है। ऐसे में प्राथमिकता रहेगी कि जो भी आदेश हो, नीति हो, नियम बनाए जाएं वे पूरे अमले की अंतिम कड़ी के आरक्षक को भी स्पष्ट रूप से पता चले। ताकि इनका परिपालन सही तरीके से होना सुनिश्चित हो सके।

नवागत कप्तान ने कहा कि, वे अभी क्षेत्र और उसकी समस्याओं को समझेंगे और उसके बाद प्राथमिकताएं तय करेंगे, क्राइम कंट्रोल के लिए आम जनता से फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को लोगों से फीडबैक लेने को प्रेरित किया जाएगा।

ट्रैफिक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि, पहले शहर का भ्रमण कर परीस्थिति को समझेंगे। आम जनता को ही सबसे अधिक समस्या का पता होता है। उन्हीं के साथ चर्चा कर समस्या समझी जाएगी, और समन्वय बनाकर समस्या का हल निकाला जाएगा। जिला प्रशासन और पूर्व एसपी गौरव तिवारी द्वारा प्रारंभ की गई गुंडो, बदमाशों के खिलाफ मुहीम आगे भी जारी रहेगी।

कम्युनिटी पुलिसिंग पर रहेगा बड़ा फोकस

नवागत एसपी ने बालाघाट के अनुभव साझा करते हुए बताया कि, वहां एंटी नक्सली आपरेशन में भी मुख्य धुरी सामुदायिक पुलिसिंग रही। रतलाम में जहां इसकी आवश्यक्ता होगी, वहां इसका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि, बालाघाट में तो लोग नक्सल विचारों से दूर रहें, इसके लिए स्वास्थ, शिक्षा तक की व्यवस्था तक पुलिस करती थी। यहां भी आम जनता को अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा।

स्टॉफ नर्सों की मनमानी से अस्पताल पहुंचने वाले मरीज हो रहे है परेशान

माही की गूंज, शाजापुर। अजय राज केवट

जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी कम होने का नाम ही नही ले रही है। यही कारण है कि, मरीज और उनके परिजनों को आए दिन स्टॉफ नर्सों के अडियल और मनमाने रवैये के कारण घंटों तक परेशान होना पड़ रहा है। अब स्टॉफ नर्सों की लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली के कारण एक धात्री महिला को घंटों परेशान होना पड़ा। दरअसल सोमवार को शाजापुर के जीवनसिंह अपनी पत्नी के ऑप्रेशन के टांके कटवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां मौजूद स्टॉफ नर्सों ने टांके काटने की बजाय महिला को इधर से उधर भगाने लगे। नर्सों की मनमानी का यह सिलसिला करीब तीन घंटे से अधिक समय तक चलता रहा।

जीवनसिंह ने बताया कि, स्टॉफ नर्सों के द्वारा टांके काटने में आनाकानी की जा रही थी और बिना वजह ही इधर से उधर दौड़ाया जा रहा था। जब घंटों परेशान होने के बाद भी नर्सों ने टांके नही काटे तो मामले में मीडियाकर्मियों को सूचना दी गई। इसके बाद नर्सों की मनमानी सिविल सर्जन डॉ. बीएस मैना के पास पहुंची, जिस पर डॉ. मैना ने नर्सों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला के ऑपरेशन टांके कटवाए।

सिविल सर्जन डॉ. मैना ने बताया कि, नर्सों को निर्देशित किया गया है कि, वे ऑपरेशन के टांके काटे जाने संबंधित तख्ती मेटरनिटी हॉल के यहां लटकाएं, ताकि मरीजों को असुविधा का सामना नही करना पड़े।

तस्कर सहित 55 किलो अवैध डोडाचूरा के साथ वाहन जप्त

माही की गूंज, रतलाम।

नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा रतलाम जिले के थाना बड़ावदा में मादक प्रदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुनील पाटीदार, एसडीओपी महोदय रविंद्र बिलवाल के मार्गदर्शन में थाना बड़ावदा पुलिस द्वारा सूचना के तहत टीम गठित कर बिट में भ्रमण के दौरान मादक पदार्थ तस्कर रुद्र प्रताप सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी शक्कर खेड़ी थाना कालूखेड़ा से 55 किलोग्राम अवैध मादक प्रदार्थ डोडा चूरा और लोडिंग वाहन क्रमांक एमपी 43 एल 2507 जब तक किया गया। उक्त मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 17/2022 धारा 8/15 का पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी रूद्र प्रताप सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा प्रकरण में जप्त से मादक प्रदार्थ मनोहर लाल बैरागी निवासी जेठाना थाना कालूखेड़ा से लाना व साबिर खा निवासी हसन पालिया के द्वारा वाहन की प्लानिंग करना बताया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह जादौन, उप निरीक्षक गोपाल बोराना, कांतिलाल सोनार्थी, भानु प्रताप पुरोहित, एलेग्जेंडर राय, जयंतीलाल पाटीदार, महेश चंद्र मिश्रा, निकोलस लाकड़ा, विवेक शर्मा, सुनीलाल, विकास गुप्ता, महेश धाकड़, ब्रजकिशोर, महेंद्र सिंह, शंकरलाल काश का सहयोग रहा।

ऑटो बाइक में भिड़ंत, राहगीर महिला हुई घायल

माही की गूंज, थांदला (झाबुआ)।

थांदला-झबुआ मार्ग पर नोगवा नदी के पार ढूहुकी माता मंदिर के निकट एक ऑटो रिक्शा व बाइक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में पैदल जा रही महिला सुखली दलिया थांदला, राकेश नानिया, जगला लालजी मानपुर घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना डायल 108 को मिलते ही घटना स्थल पहुची व घायलों को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भेजा गया।

मध्यप्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यो का सघन निरीक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा जनपद पंचायत मेघनगर में मध्यप्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कार्यो का निरीक्षण किया। ग्राम कचलदरा मेघनगर में माननीय विधायक वीरसिंह भूरिया भी उपस्थित थे। मिश्रा ने मध्यप्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मुनिया फलिया बाउन्ड्रीवाल कचलदरा जिसकी लागत 4.80 लाख है का निरीक्षण किया एवं मुनिया फलिया चेक डेम कचलदरा जिसकी लागत 19.15 लाख है का भी जायजा लिया एवं निर्देश दिए की यहां पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें। जिससे यहां का जल शुद्ध भी हो, इसी तरह ग्राम कचलदरा ग्राम पंचायत प्राथमिक शाला बाउन्ड्रीवाल जिसकी लागत 8.20 लाख है का निरीक्षण किया एवं यहां पर जो अव्यवस्था थी उसका तत्काल निराकरण तहसीलदार मेघनगर को करने के निर्देश दिए। स्कूल की बाउन्ड्रीवाल तत्काल पूर्ण करें एवं आस-पास के रहवासियों के लिए पृथक से व्यवस्थित रूप से निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम कचलदरा में बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। जिसकी लागत 14.63 लाख है। यहां पर व्यवस्था को सुधार करने के निर्देश दिए। ग्राम रामपुरा में भी मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी 108 लाख की निर्मित हो चुकी है। तत्काल आवश्यक व्यवस्थाए कर पेयजल प्रदान करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पतरा में भी मिशन के अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्र का भी अवलोकन किया एवं ग्वाली ग्राम पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक शाला बाउन्ड्रीवाल जिसकी लागत 4.85 लाख है तत्काल पूर्ण करें एवं आवश्यक बाधाए दूर करने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए।

मिश्रा ने ग्रामीणो से रूबरू चर्चा की जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं जो हितग्राही पलायन पर गए है उनसे संपर्क कर तत्काल आवास पूर्ण करें अन्यथा उनके आवास निरस्त करें और जो पात्र हो उन्हें दिया जाए। किसी भी स्थिति में राशि प्राप्त कर आवास नहीं बनाना एक गंभीर अनियमित्ता के रूप में लेकर कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान तहसीलदार मेघनगर रविन्द्र चौहान, मध्यप्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के प्रभारी अधिकारी अशोक पाटिदार, युवा सलाहकार मोहिनी मौर्या, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर अंतरसिंह डावर, उपयंत्री अमित पटेल एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

चलते डंपर में शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग

माही की गूंज, मंदसौर।

दलोदा थाना क्षेत्र में महू-नीमच फोर लाइन हाईवे के निकट अचानक चलते डंपर में आग लग गई। घटना स्थल से मिली जानकारी अनुसार यह घटना मंगलवार देर शाम बताई जा रही है। डंपर क्रमांक एमपी 14 एमबी 1739 कचनारा से मंदसौर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सरसोद फंटे के निकट डंपर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। किसी तरह चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन डंपर का केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची नगर परिषद की फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया तब तक डंपर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। दलोदा थाना पुलिस ने बताया कि, डंपर भाजपा नेता आशीष गुप्ता का है और यह कंट्रक्शन के काम में लगा हुआ था।

गौ सेवा परमो धर्म को चरितार्थ करता श्री खाटू श्याम मित्र मंडल

माही की गूंज, भानपुरा।

नगर में शासन से मान्यता प्राप्त हारे का सहारा सेवा समिति द्वारा संचालित श्री खाटू श्याम मित्र मंडल गौ सेवा समिति नगर में आए दिन नए-नए प्रकल्प से कार्य करता है। खाटू श्याम मित्र मंडल लगातार 5 वर्षों से गोवंश को चारा खिलाने का कार्य कर रहा है। यह मित्र मंडल शाम को नगर में विचरण करने वाले गौ वंश के लिए जन सहयोग से गो ग्रास की व्यवस्था करता है।

संवाददाता द्वारा जानकारी के लिए समिति के मार्गदर्शक मुकेश राठौर व अध्यक्ष सुनील माली से बात की तो उन्होंने बताया कि, हम लगातार 5 वर्षों से गौ सेवाएं करते आ रहे हैं जिसमें नगर वासियों के जन सहयोग से यह कार्य किया जाता है। नगरवासी अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, मांगलिक कार्य, जन्म जयंती, पुण्यतिथि पर समिति के सदस्यों से संपर्क कर गौ सेवा का लाभ लेते हैं।

बता दें कि, अभी तक समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में निराश्रित, मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था की व पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 5 हजार सीट बॉल का निर्माण समिति के मार्गदर्शक शिक्षक मुकेश राठौर के मार्गदर्शन में किया। वही ग्रीष्म काल में सकोरा अभियान चलाकर पक्षियों के लिए सकोरे लगाए जिससे पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। सकोरा अभियान में लगभग 500 से 600 सकोरे समिति द्वारा भानपुरा तहसील क्षेत्र व अन्य स्थानों पर लगाए गए। ठंड में असहाय जनों के लिए पहल कर जन सहयोग से कंबल वितरण भी किया, जिसमें लगभग 800 से 900 कंबल समिति द्वारा वितरित किए गए। वही समिति के सदस्यों ने गर्म कपड़ों का वितरण भी किया। इन कार्यों को करने के लिए नगर वासियों का महत्वपूर्ण योगदान व समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों, मार्गदर्शक मुकेश किशन राठौर, अध्यक्ष सुनील माली, उपाध्यक्ष गौरव श्रीमाल, ऋषभ बैरागी, सचिव, लोकेश राठौर, सह सचिव अमन सोनी, विनायक मंडकरिया, कोषाध्यक्ष अर्पित चंदेसिया, महामंत्री शरद बंबोरिया, संगठन मंत्री नवनीत गौतम, अलंकृत राठौर, मीडिया प्रभारी आशुतोष लक्षकार, कपिल विश्वकर्मा, भरत दगदी, ऋतिक भाना, व्यवस्था प्रमुख राकेश माली, मृणाल राठौर, ललित नरवालिया, पूजा-पाठ प्रभारी रवि जोशी, समिति सदस्य आयुष राठौर, रजत राठौर, मोहित राठौर, हिमांशु राठौर, मनीष राठौर, उमेश राठौर, दीपक धाकड़, रवि पाटीदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

न्यूज ब्रीफ

एक पटवारी निलंबित, 10 की वेतन वृद्धि रोकने के किए जारी आदेश

माही की गूंज, खरगोन।

एसडीएम मिलिंद ढोके ने खरगोन तहसील के हल्का नं. 2 दसंगा के पटवारी विनोद बर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसडीएम श्री ढोके ने बताया कि, पटवारी विनोद बर्वे द्वारा गिरदावरी में शुन्य क्षेत्रफल, लघु सिंचाई, सगंणना, स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी सर्वे में पान्यादड व बगवा की आरआरओ इंट्री पूर्ण न करना तथा रिकार्ड शुद्धिकरण एवं डेट परिमार्जन में शत-प्रतिशत कार्य न करना लापरवाही किये जाने पर यह कार्रवाई की गई है। पटवारी मुख्यालय पर भी निवास नहीं करते हैं। निलंबन अवधि में पटवारी बर्वे का तहसील मुख्यालय गोगांवा रहेगा।

इसके अलावा अंकित शाह पटवारी हल्का नंबर 37 बीजापुर, किशन बडोले पटवारी हल्का नंबर 1 भड़ली, महेश पाटिल पटवारी हल्का नंबर 34 गांव सन, कंचन पांडे पटवारी हल्का नंबर 28 गोटिया, कमल खुटे पटवारी हल्का नंबर 38 डोंगरचीचली, कुलदीप यादव पटवारी हल्का नंबर 26 पनाली तहसील सेगाव, किशोरी लाल फुल पगारे पटवारी हल्का नंबर 9 जमोठी तहसील सेगांव, बद्रीलाल कनोजे पटवारी हल्का नंबर 13 गोवाडी तहसील गोगावा, प्रदीप मंडलोई पटवारी हल्का हल्का नंबर 22 नागझिरी तहसील गोगावां द्वारा रबीफसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने पर दो-दो वेतन वृद्धि रोकी जाने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वेटलैंड दिवस एवं जल जागरण अभियान पर युवाओ को दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

नेहरू युवा केंद्र बड़वानी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना बड़वानी के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के अपर हॉल में जल जागरण अभियान पर युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला संगठक आरएस मुजाल्दे एवं जिला युवा अधिकारी नितेश कुमार ने समस्त छात्रों से अपील की, कि वह पानी की बचत करें। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जल की बचत करने के बारे में जागरूक बनाना है और कम से कम जल का दोहन करने के लिए प्रेरित करना है।

डॉ. रंजीत सिंह मेवाडा ने छात्रों को बड़वानी के आसपास के क्षेत्र में जल संग्रहण के तरीकों की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पूर्वज कैसे जल का संग्रह एवं इस्तेमाल करते थे इस बारे में बताया। डॉ. श्वेता कटिहार ने छात्रों को वर्षा के जल को संग्रह करने के प्रमुख तरीके एवं देश में चल रहे नए तरीके के बारे में जानकारी दी । डॉ राजमल सिंह राव ने बारिश के पानी को कैसे उपयोग में ले सकते है, इस बारे में बताते हुए पानी की बचत कैसे करना चाहिए इस बारे में बताया।

जल संरक्षण की दिशा में मनरेगा की अहम भूमिका

माही की गूंज, खरगोन।

विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाली महात्मा गॉधी रोजगार गारंटी योजना से दो तरफा लाभ हो रहा है। एक तो जरूरतमंद लोगो को गॉव में ही रोजगार तथा दूसरी ओर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो पा रही है। हम बात कर रहे है कुछ ऐसे कार्यो की जो मनरेगा से हुए है और ग्रामीण जनता को शत प्रतिशत फायदा हो रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी. दूर स्थित लाखी गांव में सर्दी के दिनों से ही पेयजल की समस्या सामने आने लगती थी। लाखी के लोग सिर्फ इसलिए खुश नही है कि, अब गर्मी में पानी की समस्या नही होगी। बल्कि इसलिए भी वे खुश है कि करीब 200 किसानों के कुएं और 50 ट्यूबवेल स्टॉप डेम से रिचार्ज होने लगे है। जिस गांव के लोग गर्मी का नाम सुनते ही पानी के संकट से घबराने लगते थे। उस गांव के लोग आज पेयजल को लेकर आश्वस्त हो गए है। इनके आश्वस्त होने का एक छोटा सा कारण है स्टॉप डेम। स्टॉप डेम तो उनके गांव में 15 वर्षो से है लेकिन अनुपयोगी मानकर स्टॉप डेम से हजारों बार गुजरे। आखिरकार विश्व मे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना से उस चेक डेम का जीर्णोद्धार हो गया।

2 घंटे सिंचाई करने वाले कुएं अब 4 घंटे तक दे रहे साथ

लाखी के ओमप्रकाश शर्मा का कहना है कि, पुराने टूटेफूटे स्टॉप डेम पर आंशिक काम करने के बाद हमारे खेतो में गेहूं, चना, मिर्च, प्याज और सब्जियों की फसलें लहलहाने लगी है।

धर्मेंद्र कुशवाह का कहना है कि, जब ये डेम का काम नही हुआ तो मुश्किल से उनके कुएं पर लगी 3 हॉर्स पॉवर की मोटर 2 घण्टे चल पाती थी लेकिन अब 4 घंटे भी आराम से सिंचाई करने लगे है। नाले के सहारे इंदिरा सागर का पानी नहर में छोड़ा जाता था। जो नाले से सीधे बह जाता था, सिर्फ मोटर पंप चलाकर ही सिंचाई कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गॉव के रोजगार सहायक दीपक ने बताया कि गॉव में 15 वर्ष से बना एक स्टॉप डेम है जो पूरी तरह अनुपयोगी था। इस स्टॉप डेम पर मात्र 48 हजार रूपये से शटर और कुंडिया लगाई गई और नाले की साफ-सफाई कर गहरीकरण किया गया। आज यह स्टॉप डेम गॉव की उन्नती मार्ग बन गया है। मनरेगा के परियोजना अधिकारी श्याम रघुवंशी ने बताया कि मनरेगा के तहत् जिलें में 1112 तालाबों, स्टॉप डेम और चेक डेम का जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ किये गये है।

नदी के जल को शुद्ध रखने में उपयोगी है डब्ल्यूएसपी

हर गाँव या छोटे-छोटे कस्बों में कई नालियॉ होती है जिसके सहारे गाँव या नगर की गंदगी और गंदा जल बहकर जाता है। जो किसी एक स्थान पर जाकर एक मुख्य नाली में बदल जाती है। ऐसे स्थान पर मनरेगा के तहत् जल स्थरीकरण के प्लांट विकसित किये जा रहे है। इन प्लांटस में सारा गंदा पानी और गंदगी एकत्रित होती है। क्योंकि जल एक स्थान पर एकत्रित होता है इसलिए जल के साथ बहकर आई गंदगी जमीन की सतह में बैठ जाती है। इसमें तीन टैंक होते है। एक टैंक में पानी भरने के बाद दूसरे और फिर तीसरे टैंक में पानी अपनी गंदगी छोड़ कर या यू कहें कि शुद्व होकर आगे निकल जाता है। इसका लाभ यह है कि नदी में मिलने वाला जल शुद्व होता है। जिले में ऐसे 106 डब्ल्यूएसपी स्वीकृत हुए है। जिसमें 2 पूर्ण हुए है। जबकि 71 प्रगतिरत है।

मलेरिया डेंगू जैसी बिमारियों से बचाने में सोख पीठ का योगदान

मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिलें में 2 हजार 346 सामुदायिक सोख पीट, हैंडपंप सोख पीट और लीच पीट बनाने का लक्ष्य है। जिसमें से अब तक 647 बनकर तैयार हो गए है। ये स्ट्रक्चर ऐसे स्थानों पर बनाए गए है जहाँ हमेशा गंदा पानी एकत्रित रहता है। जैसे हैंड पंप के आसपास या कुडाकरकट वाला क्षेत्र होता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे स्त्रोत से जोड़ दिए जाते है। जिससे गंदगी भी दूरी होती है और जल भी जमीन में जाता है। खासकर गॉवों में एक स्थान पर गंदे जल में कई प्रकार के मच्छर और कीड़े पनपते है। ऐसे स्ट्रक्चर से मलेरियॉ और डेंगू जैसी बिमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांक सिंह ने बताया गया कि 2 फरवरी 2005 को मनरेगा अधिनियम लागू हुआ था। आज इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ रोजगार उपलब्ध हो रहे है बल्कि कई आधारभूत संरचनाएँ बनकर तैयार हुई है। इसमें जल संरक्षण और स्वच्छता में बड़े अच्छे परिणाम देखने में आ रहे हैं।

एक दिन में आए कोरोना के 381 मरीज

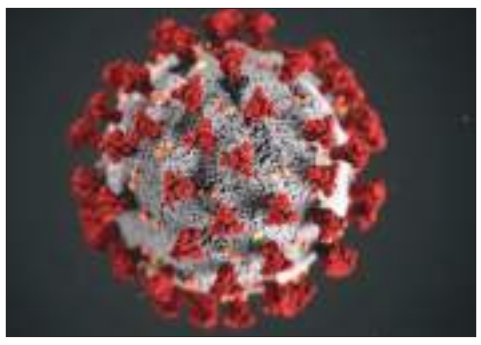

माही की गूंज, खरगोन।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा बुधवार को हैल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को जिले में 381 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जबकि 831 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जिले में अब कुल एक हजार 851 मरीज स्थिर है। इनमें 5 मरीज अस्पताल में और एक हजार 846 मरीज होम आयसोलशन में हैं। वहीं 312 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में अब तक कुल 18 हजार 497 मरीज पॉजिटिव हुए हैं। जिनमें से 16 हजार 290 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं जिले में अब कुल 45 हजार 7051 व्यक्तियों के सेम्पल लिए गए हैं। जिसमें से 43 हजार 6159 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है।

मृतकों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 356

डॉ. आरआर कोसले द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 73 वर्षीय रमेश हरीश जमालपुरा बड़वाह को सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या को लेकर 24 जनवरी को गुर्जर हॉस्पिटल बड़वाह में भर्ती हुआ था। 25 जनवरी को रमेश का आरटी पीसीआर टेस्ट लिया गया था। 26 जनवरी को रमेश की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। ज्ञात हो कि, मृतक रमेश की 28 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई थी। मृतक पूर्व से ही हाइपरटेंशन तथा लिवर इन्फेकशन से ग्रसित था। एक मरीज की मृत्यु से अब जिले में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 356 हो गया है।

कलेक्टर ने किया दीनदयाल रसोई केन्द्र का निरीक्षण

पैकेट के स्थान पर बैठाकर खिलाने के लिए दिए निर्देश

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने जिला मुख्यालय पर संचालित दीनदयाल रसोई केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जहॉ उन्होने रसोई केन्द्र में तैयार भोजन सामग्री को चखकर देखा एवं उसकी गुणवत्ता को सही पाया, वहीं रसोई केन्द्र का संचालन करने वाले लायंस क्लब के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अब रसोई केन्द्र से पैकेट वितरण के स्थान पर पूर्व के समान टेबल-कुर्सी पर बैठाकर भोजन करवाया जाये। साथ ही कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित नगरपालिका सीएमओ कुशलसिंह डोडवे को भी निर्देशित किया कि, वे शहर में विभिन्न स्थानों पर दीनदयाल रसोई केन्द्र के फ्लेक्स लगवायेंगे। जिससे राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब बन्धु एवं फेरी लगाने वाले उठा सके ।

अचानक रसोई केन्द्र पहुंचे कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान जहॉ बने हुये भोजन सामग्री की गुणवत्ता को देखा, वहीं स्टोर्स रूम में सग्रहित खाद्यान्न सामग्री का भी निरीक्षण कर खाद्यान्न को और व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये । जिससे खाद्यान्न सामग्री मौसम के परिवर्तन से पूरी तरह सुरक्षित रह सके, वहीं चूहे भी उसे नष्ट न करने पाये। साथ ही कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित नगर पालिका सीएमओं एवं केन्द्र संचालन करने वाले पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे केन्द्र के बाहर अस्पताल परिसर एवं शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर रसोई केन्द्र की जानकारी युक्त फ्लेक्स लगवायेंगे। जिससे नाम मात्र के शुल्क पर मिलने वाले इस भोजन सामग्री को गरीब एवं फेरी लगाने वाले लोग तथा अस्पताल में भर्ती रोगियों के दूर-दराज क्षेत्रों से आये परिवार के लोग उठा सके ।

इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि, अब केन्द्र से पैकेट के स्थान पर केन्द्र पर ही टेबल-कुर्सी पर बैठाकर खिलाने की व्यवस्था पूर्व के समान करें, किन्तु इस दौरान सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन भी अनिवार्य रूप से करवायें।

स्वच्छता को लेकर सक्रिय हुए एसडीएम

माही की गूंज, बड़वानी।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी नगर निकायो को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के दिये गये निर्देश पर जिले में भी द्रुतगति से कार्यवाही प्रारंभ है। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा के निर्देश पर जिले में भी फरवरी माह को स्वच्छता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान में जिले के समस्त एसडीएम भी सहभगिता कर अपनी देखरेख में नगर में स्वच्छता का कार्य करवा रहे है।

इसी क्रम में राजपुर एसडीएम वीरसिंह चैहान ने भी मंगलवार की प्रातः काल नगर परिषद के सफाई अमले को लेकर सफाई अभियान प्रारंभ करवाया। इस दौरान उन्होंने नगर के मध्य से बह रही रूपा नदी में पसरी गन्दगी को साफ कराया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता निरीक्षक श्री योगेश गुप्ता को निर्देश दिए कि नगर में मुनादी कराकर नगर वासियों को सूचना दी जाए कि, दुकानदार और नगरवासी कचरे को डस्टबिन में इकट्ठा करें और उसे कचरा वाहन में डालें । जो भी कचरा खुले में फेंककर गन्दगी फैलाता है उस पर चालानी कार्रवाई कर अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा। एसडीएम श्री चैहान ने नदी किनारे बसे पशुपालकों से भी चर्चाकर उन्हें समझाईश दी कि वे घर के सामने से गोबर के रुखड़े हटा ले, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी।

इस दौरान एसडीएम वीरसिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों से आव्हान किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जा रहा है। अतः वे भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराये। जिससे राजपुर नगर को देश का सबसे स्वच्छ नगर बनाया जा सके।

किसान उत्पादक संगठन करें किसान हित में कार्य- कलेक्टर वर्मा

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने जिले के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आव्हान किया कि हम सभी मिलकर किसान हित में कार्य करे। जिससे जिले के छोटे किसानों को उन्नत खेती के संसाधनों का लाभ सहजता से मिल सके। और वे अपनी आय को दुगुनी कर, क्षेत्र विकास में अपना योगदान दे सके।

इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों नेचर टू अर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमि. तलवाडा बुजुर्ग, पाटी रूरल लिवली हूड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, आगा खांन रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सेंधवा, आसा सेंधवा एवं मंथन एनजीओ द्वारा पॉवर पाईंट प्रेजेटेंशन कर अपनी गतिविधियों से उपस्थितों को अवगत करवाया गया।

इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि, एफपीओ का एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए । ज्ञान के अभाव में किसानों का शोषण नही होना चाहिए। एफपीओ द्वारा सभी नियमों की समुचित जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए। किसानों में आपसी विश्वास पैदा करने हेतु प्रत्येक गांव में एक अग्रणी किसान को लीडरशीप देना होगा। जिससे वे कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को भी दिलवा सके। इस दौरान कलेक्टर ने एफपीओ के पदाधिकारियों को बताया कि, सभी परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करते हुए किसानों के हित को प्राथमिकता दें।

बैठक के दौरान उप संचालक कृषि आरएल जमरा ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य पाटी, सेंधवा व निवाली विकासखण्ड में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का बहुत अल्प उपयोग किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित किये जाने का भरपूर अवसर है।

बैठक के दौरान उप संचालक उद्यानिकी विजयसिंह ने बताया कि, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के तहत अदरक के साथ द्वितीय उत्पाद के रूप में मिर्च को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

उक्त समीक्षा बैठक में उप संचालक कृषि श्री आर.एल. जमरा, उप संचालक उद्यानिकी विजयसिंह, सहायक संचालक कृषि आर.के. सिंगारे एवं एस.एल. पंवार के साथ विभिन्न किसान उत्पाद संगठनों के संचालक /प्रतिनिधि के रूप में चंद्रशेखर चैहान, मोहम्मद रशीद शेख, दिव्या खण्डेलवाल, सुनिल यादव व गजेन्द्रसिंह पंवार उपस्थित थे।

बेडमिंटन कोर्ट की नेट का शुभारंभ कर खेत गतिविधि प्रारंभ

माही की गूंज, झाबुआ। मंगलवार की सायं कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन के द्वारा मिण्डल स्थित बेडमिंटन कोर्ट में नेट का शुभारंभ फिता काटकर किया एवं यहां पर विधिवत बेटमिंटन खेल का शुभारंभ किया। जिले के लिए यह बडी सौगात पूर्व में माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अब नियमित रूप से यहां पर खेल प्रारंभ हो चुका है। जिले के बेडमिंटन कोर्ट की एक बेहतरिन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिसे बेडमिंटन खिलाडी इसका उपयोग करें एवं जिले का नाम रोशन करें। इस आयोजन में श्री उमंग सक्सेना, श्री विवेक पेंटर, श्री प्रदीप जैन, श्री मनोज बाबेल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया एवं अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में कहा की यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है उसका भरपूर उपयोग करें।

इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ अर्पित गुप्ता, डॉ. राहुल गणावा, सोहेल, सुधीर तिवारी, डिस्टीक कमांडेन्ट होमगार्ड गुलाबसिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एल.एस.डोडिया, एजाज कुरेशी, संजय शाह, जामसिंह अमलियार, जैन एवं त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए है...

देर रात तक चली भजन संध्या भजनों पर जमकर थिरके श्रद्धालु

माही की गूंज, नानपुर। फिरोज पठान

राठौड़ समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी स्व. राजेंद्र राठौड़ (राजू भाई) की स्मृति में आयोजित भजन संध्या में देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर जमकर थिरके। स्व. राजू भाई के परिजनों द्वारा उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर भजन संध्या एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें खरगोन के भजन मंडल ग्रुप के पीयूष कुशवाह, सुश्री मेघा परसाई व शुभम तारे द्वारा प्रस्तुत आकर्षक व शानदार संगीतमय भजनों से श्रोताओं को जमकर झूमने पर मजबूर कर दिया। एक और उन्होंने दहेज जैसे अन्य विषय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार पर अपने भजनों के माध्यम से सुंदर संदेश भी दिया, वहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रहार किया।

उक्त भजन संध्या में खट्टाली, जोबट, अलीराजपुर, कुक्षी, मनावर, गंधवानी, आंबुआ आदि स्थान से बड़ी संख्या में श्रोतागण एवं राठौड़ समाज जन सम्मिलित हुए।उक्त कार्यक्रम में बालीपुर से श्री श्री 1008 संत श्री योगेश जी महाराज भी पधारे। उन्होंने इस अवसर पर राजू भाई राठौड़ के परिवार को सांत्वना एवं आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही गुरु भक्तों ने उनके दिव्य दर्शन का लाभ लिया। भजन के दौरान महिलाओं ने जहां गरबा रास खेला तो वहीं पुरुषों ने अलग-अलग भाषाओं में गाए भजनों पर समूह नृत्य से समां बांध दिया। प्रसिद्ध भजनों में ''क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे'', ''तेरे बिना श्याम'', ''गुरुदेव कृपा करना'', ''ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन'', ''सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए है'' आदि सहित निमाड़ी व मालवी भजनों की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम के आरंभ में राजू भाई को श्रद्धांजलि के साथ आए हुए कलाकारों का स्वागत किया गया। साथ ही उनके मित्रों, परिजनों द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपनी बात रखी। आरंभ में परिजनों एवं सभी उपस्थित जनों ने बालीपुर सरकार ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और गुरु आरती के साथ गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। अंत तक श्रोताओं ने अपनी पसंद के भी कई भजन की फरमाइश कलाकारों से की। देर रात 3 बजे तक आयोजित भजन संध्या में कड़ाके की ठंड के दौरान भी महिला पुरुष डटे रहे। अंत में पधारे संत सहित सभी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का शानदार संचालन प्रदीप क्षीरसागर ने किया एवं आभार राहुल राठौड़ ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में नानपुर के सभी समाज जन, संस्था, संगठन एवं कलाकारों ने अपनी उपस्थिति प्रदान कर राजू भाई की स्मृति को नमन किया।

आखिर कब बनेगा शासकीय कृषि महाविद्यालय

माही की गूंज, थांदला (झाबुआ)।

कृषि प्रधान जिले में आदिवासी बालक-बालिका हेतु 11वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होने से छात्र-छात्राएं अन्य विषय लेना स्वयं की मजबूरी मानते हैं। जिले में वर्ष 1999 के विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में थांदला प्रवास पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, उक्त घोषणा पर आज पर्यंत तक अमल नहीं हुआ है और अंततः दिग्विजय सिंह घोषणा वीर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। 2003 में चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा सत्ता पर आज पर्यंत तक का बीज है, उनके कई मुख्यमंत्री इस जिले के दौरे पर आए किंतु इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इस संदर्भ में पड़ताल करने पर पाया कि, प्रशासन शासकीय जमीन का ना होने का हवाला देकर अपने कर्तव्य से विमुक्त होता रहा।

शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करें तो नगर से 2 किलोमीटर दूर ग्राम खजूरी में कृषि विभाग की सरदार सरोवर के विस्थापितों हेतु आरक्षित जमीन जिस पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने स्वयं उपस्थित होकर विस्थापितों से उक्त जमीन लेने से इनकार कर दिया था। वह जमीन आज भी विस्थापितों हेतु रखी है, शासन इस जमीन पर अन्य लोगों को बसाने की योजना बनाए उसके पूर्व उक्त जमीन पर शासकीय महाविद्यालय हेतु आवंटित कर दी जाए तो यह छात्रों के हित में होगा। प्रदेश सरकार जननायक बिरसा मुंडा टंट्या मामा भील के नाम पर कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ वर्ष का समय बचा है, ऐसे में युवा आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का अनूठा प्रयास सफल होगा। वही इन महापुरुषों के नाम यदि कृषि महाविद्यालय की घोषणा शासन करती है तो, इन महापुरुषों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी व आदिवासी वोटों का बिखराव भी रुकेगा।

पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण जोन इंदौर जिले में एक दिवसीय प्रवास पर

माही की गूंज, अलीराजपुर। पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण जोन इंदौर राकेश गुप्ता एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर आए। पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंचे गुप्ता का एसपी मनोज कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेट कर स्वागत किया। पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण जोन इंदौर के द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के उपस्थित समस्त राजपत्रित एवं थाना प्रभारियों से परिचय प्राप्त किया। पश्चात पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा जिले का परिचय, भोगोलिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं जिले के अपराध परिदृश्य को प्रजेण्टेशन के माध्यम से श्री गुप्ता अवगत कराया गया। आईजी राकेश गुप्ता ने अवैध गतिविधियों पर सूक्ष्म निगाह रखनें एवं ऐसे तत्वों के विरूद्ध कठौर व प्रभावी कार्रवाई करने निर्देश दिए। अपराध एवं अपराधियों पर सख्ती बरतनें के संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अलीराजपुर पुलिस के द्वारा सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण एवं गुम इंसानों को खोजनें में जिला अलीराजपुर की म.प्र. में उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए पुलिस को बधाई देते हुए आगे भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रौत्साहित किया। आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के दौरान थाना प्रभारी आवश्यक तैयारी कर लेवें व किसी भी स्तर पर असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जावें। कानून व्यवस्था हेतु बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिला अलीराजपुर में रोजगार एवं शिक्षा के स्तर को देखते हुए पुलिस उच्चकोटी का मानवीय दृष्टिकोण बनाये व समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाए व बच्चों पर होनें वाले अपराधों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

कांग्रेस का घर-घर चलो अभियान का ग्राम गिराला से हुआ आरंभ

पार्टी की रिति-नितियों से ग्रामिणों को कराया अवगत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

मप्र कांग्रेस कमेटी के आहवान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्धारा अलीराजपुर ब्लॉक के ग्राम गिराला मे घर-घर चलो अभियान का शुभारंभ जिला कांग्रेस प्रभारी अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर द्वारा किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने ग्रामिणजनो को कांग्रेस की रिति-नितियों से अवगत कराया। वही घर-घर चलो अभियान के अंतर्गत ग्राम के सेकडो कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर घर-घर पहुंचकर सदस्यता अभियान चलाकर सेकड़ो सदस्यों को पार्टी से जोड़ा। इस अवसर पर बडी संख्या मे कांग्रेसी नेता-कार्यकर्ता व ग्रामिणजन मोजुद थे।

गरीब वर्गो की पार्टी है कांग्रेस

घर-घर चलो अभियान अंतर्गत ग्राम गिराला मे शुभारंभ सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, गरिब, दलित, आदिवासी सहित सर्वधर्म समाज हितेषी पार्टी है। पार्टी के नेता पं. जवाहलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश हित के लिए योगदान ओर बलिदान दिए है। श्री राठौर ने कहा कि, हमारी कमलनाथ की सरकार ने पिछले 15 माह मे कई महत्वपुर्ण ओर लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागु कर उसका क्रियांवयन कर अतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस किसान एवं गरिब वर्गो का भला करने वाली पार्टी है। श्री राठौर ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की जनविरोधी नितियों से ग्रामिणजनो को अवगत कराते हुए बताया कि, आज देश मे महंगाई, पेट्रौल-डिजल, रसोई गैस, खादय तेलो की बढती किमतो ने आमजनो की कमर तोड दी है। बढती हुई महंगाई को लेकर देश मे हाहाकार मचा हुआ है। जनता अपने आप का ठगा हुआ सा महसुस कर रहे है। आप लोगो की सहयोग से आगामी 2023 मे मप्र मे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि खुर्शीद अली दिवान, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र टवली, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सुरैन्द्र चोहान, मंडलम अध्यक्ष धनसिंह चोहान, वरिष्ठ कार्यकर्ता (बुथ 91-92) नवलसिंह चैहान, प्रकाश बघेल, दरयावसिंह चैहान, भीमसिंह कामत, पिरला चैहान, सुरेश चैहान, लालसिंह, राजु सहित बडी संख्या मे कार्यकर्ता व ग्रामिणजन उपस्थित थे।

नगरपालिका कर रही स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 स्वच्छता संकल्प माह का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

नगरपालिका परिषद् झाबुआ द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 के अंतर्गत स्वच्छता संकल्प माह मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे है।

जनाकारी देते हुए नपा के सीएमओ एलएस डोडिया ने बताया कि इस दौरान विगत 26 से 31 जनवरी तक जीओ मेपिंग हेतु वार्डों में सीमांकन, अपशिष्ट प्रसंकरण सुविधाएं, एफएसटीपीसी के तहत नाले-नालियों और तालाब को सम्मिलित कर जीओ मैपिंग का कार्य किया गया। डंप साईड रेमिडेशन का एक्शन प्लान बनाया गया। शहर के नागरिकों से स्वच्छता एप डाउन लोड कर शिकायतों का निराकरण करवाया गया। सी एंड डी हेतु प्लेटफार्म निर्माण कर कलेक्शन पाइंट बनाया गया। स्वास्थ्य अधिकारी यूनूसउद्दीन कुरैशी ने बताया कि स्वच्छता संकल्प माह के तहत फरवरी माह के अंत तक विभिन्न थीमों पर सत्त कार्य किया जाएगा।

बुस्टर डोज पूरी तरह सुरक्षित और कारगर, जिले के पेंशनरों से की यह अपील

माही की गूंज, झाबुआ।

कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से निपटने के लिए कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों, वालेंटियर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को भी प्री-कॉशन (बुस्टर) डोज लगने का कार्य जोर-शोर से चल रहा है।

इसी क्रम में सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व संभागीय संयोजक गोपालकृष्ण शर्मा निवासी गोपाल कॉलोनी ने भी अपनी धर्मपत्नि श्रीमती मधुलता शर्मा के साथ शासकीय बुनियादी हाईस्कूल के समीप बने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर प्रीकॉशन डोज (बुस्टर डोज) लगवाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इससे पूर्व शर्मा दंपति को वैक्सीन के दोनो डोज भी लग चुके है।

बुस्टर डोज भी जरूर लगवाएं

शर्मा दंपति ने जिलेवासियों को अपने संदेश में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी लोग वैक्सीन के दोनो डोज के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त महिला-पुरूष बुस्टर डोज भी नियत समय पर जरूर लगवाए। इसका कोई साईड इफेक्ट नहीं है। यह पूरी तरह सुरक्षित और कोरोना से रोकथाम का कारगर उपाय है।

गौरक्षा समिति ने किया एक रूपया प्रतिदिन प्रति परिवार के कार्य का शुभारंभ

हिन्दु, मुस्लिम, बोहरा समाज सभी मिलजुल कर रहे सहयोग

माही की गूंज, अलीराजपुर।

गौरक्षा समिति के सदस्य रामेश्वर दिक्षित द्वारा पुज्य गुरूदेव के चित्र पर माल्यापर्ण एवं पुजन कर किया गया। इस अवसर पर गोविन्द भाई परिहार द्वारा उपस्थित गौभक्तों से इस कार्य में सहयोग करने का आव्हान किया गया। उपस्थित गौभक्तों जिनमें हिन्दु, मुसलमान तथा बोहरा समाज के लोगों ने दान देने की घोषणा की। इस अवसर पर बोहरा समाज के बाकिर बोहरा, नफीस लातिफ बोहरा, गाँधी मेहंदी बोहरा, इब्राहीम बोहरा, अजगर बोहरा एवं मुस्लिम समाज से शेख साकिर अली, रूबी वॉच मोहम्मद बलोच, सलीम, स्टाम्प वेण्डर आदि गौभक्तों ने एक रूपया प्रतिदिन प्रति परिवार दान देने का संकल्प लिया। देखते ही दान देने वालों की होड़ लग गई तथा एक हजार लोगों ने दान देने की घोषणा की तथा इस अवसर पर छह लाख पच्चीस हजार रूपये एकत्रित हो गये।

इस अवसर पर समिति के सदस्य कैलाष राठौड़ केशव नगर ने कहा कि, गौरक्षा में जनसहयोग के अपार उत्साह को देखते हुये इस वर्ष नौ लाख रूपये एकत्रित हुये जो कि गुरूदेव द्वारा संचालित गौषाला में घास पानी दवाई में व्यय की जावेगी।

इस अवसर पर बोहरा बाकीर अली एवं शेख शाकिर अली ने कहा कि, हमारे नगर के लिये यह गर्व की बात है कि समिति द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जो कि सराहनीय कार्य है। यहाँ हिन्दु मुस्लिम बोहरा समाज सभी मिलजुल कर सहयोग प्रदान करते है। जिससे भाईचारे का संदेष जाता है।

इस अवसर पर गायत्री परिवार के ग्यारसीलाल भाटीया ने समिति के इस शुभ कार्य के लिये समिति को बधाई दी। इस अवसर पर डावर बस सर्विस से रामुभाई डावर, नगरपालिका अध्यक्ष रितेष डावर द्वारा अपनी बस के समस्त स्टॉफ को 20 रूपया प्रतिदिन देने का संकल्प दिलाया। इस प्रकार एक वर्ष में तीस हजार रूपये एकत्रित होंगे।

इंदौर संभाग के सभी नगरीय निकाय सीख रहे हैं कार्बन क्रेडिट का ककहरा- संभागायुक्त डॉ. शर्मा

माही की गूंज, अलीराजपुर।

इन्दौर संभाग के सभी नगरीय निकाय कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के सभी जतन करेंगे। सभी निकाय कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन पर काम करेंगे। कार्बन क्रेडिट के अंक अर्जित कर अतिरिक्त आय भी प्राप्त करेंगे। संभागायुक्त और इंदौर नगर निगम के प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा की पहल पर इंदौर संभाग के सभी नगरीय निकायों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ ऋषव गुप्ता ने उन्हें अपने प्रजेंटेशन से इस संबंध में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की प्रक्रिया से भी उन्हें अवगत कराया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अपर आयुक्त रजनीश कसेरा एवं संभाग के सभी नगरीय निकायों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे।

संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि, सभी नगरीय निकाय कचरा पृथक्कीकरण प्रक्रिया की शुद्धता पर ध्यान दें। ऐसे सभी उपाय सुनिश्चित करें, जिनसे कि कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन कम होता है। स्मार्ट सिटी द्वारा इस संबंध में दस्तावेजीकरण और अन्य सभी तरह की उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है और हम सभी के समेकित और छोटे-छोटे प्रयासों से आने वाले समय में हम कार्बन का उत्सर्जन कम करने में सफल होंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्बन रेटिंग क्रेडिट कैसे ले सकते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषव गुप्ता ने बताया कि, स्मार्ट सिटी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के समय लगभग 70 हजार कार्बन क्रेडिट अर्जित कर 9 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। इंदौर इस तरह आय अर्जित करने वाला देश का पहला शहर है। इंदौर संभाग के अन्य नगरीय निकाय भी ऐसा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खंडवा और बुरहानपुर के नगर निगम आयुक्त सहित धार, मनावर, पीथमपुर, खरगोन सनावद, बड़वाह, सेंधवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, नेपानगर, धामनोद, राऊ, सांवेर बेटमा, गौतमपुरा, देपालपुर, हातौद, मानपुर और महू गाँव के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सम्मिलित हुए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऋषव गुप्ता ने बताया कि, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट अपनाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। रिन्युअल एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत सोलर रूप टॉप और स्माल स्केल हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। ऊर्जा दक्षता प्रोजेक्ट के तहत एलईडी लाइटिंग प्रोजेक्ट अपनाए जा सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन ईंधन का प्रयोग कम करके परिवहन के ऐसे माध्यम जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य साधनों का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। ठोस कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बायो गैस आधारित प्रोजेक्ट और एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट अपनाकर भी कार्बन क्रेडिट अर्जित की जा सकती है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक एकत्रीकरण और रिसाइक्लिंग पर भी ध्यान दिया जाना होगा। उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन मिटिगेशन मैकेनिज्म अपनायी जानी चाहिए।

इंदौर स्मार्ट सिटी के साथ खरगोन, बड़वाह और सनावद नपा करेगी एमओयू

खरगोन नगर पालिका के साथ-साथ बड़वाह और सनावद नगर पालिका भी कार्बन क्रेडिट को लेकर इंदौर स्मार्ट सिटी के साथ एमओयू करेगी। खरगोन शहरी परियोजना अधिकारी श्रीमति प्रियंका पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि, स्मार्ट सिटी इंदौर ने संभाग की नगर पालिकाओं के साथ कार्बन उत्सर्जन को लेकर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऐसी नगर पालिकाएं जो अपने नगर के कचरे का निपटान उचित तरीके से करना चाहते है। लेकिन प्रारम्भिक स्थिति में समस्याएं होने से कार्य प्रारम्भ नही हो सका है। इसके लिए स्मार्ट सिटी अपनी तरफ से सारी सुविधाएं जैसे पंजीयन या अन्य तरह से सहयोग करेगी। जिससे नगर पालिकाएं कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

धार जिले के नगरीय निकाय भी बनाएंगे कार्ययोजना

धार के डिप्टी कलेक्टर एवं पीओ डूडा राहुल चौहान ने बताया कि, धार जिले के मनावर, पीथमपुर, धमनोद और धार नगरीय निकायो में कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए पेड़ लगाने, एलईडी लाईट का उपयोग, सोलर पैनल लगाने, कचरे का व्यवस्थित प्रबंधन करने की कार्ययोजना बना कर अमल में लाने की योजना है। इसके साथ ही प्लास्टिक का रीसाइक्लिंग, कचरे से बॉयोगैस बनाना आदि वे सभी गतिविधिया जिनसे कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित कर सके किया जाना प्रस्तावित है ।

डीजल माफिया रामपाल से प्रशासन का यह रिश्ता क्या कहलाता है...?

जिले के सारे अवैध डीजल के ठीकाने बंद, माफिया रामपाल काट रहा चांदी

युसूफ की नहीं गल रही दाल, प्रशासनिक कार्यप्रणाली अब भी संदेह के घेरे में

माफिया रामपाल का अवैध डीजल का पंप छापरी में अब भी बदस्तूर जारी है।

खजूरखो में दिन में सन्नाटा पसरा रहता है लेकिन रात में यहां हलचल बढ़ जाती है।

रात के अंधेरे में होने वाली हलचल की गवाही देते बड़े वाहनों के टायरों के निशान।

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले कई महीनों से माही की गूंज ने अवैध डीजल माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। दबाव में आकर ही सही लेकिन प्रशासन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। नतीजा कुछ यूं है कि जिले में अवैध डीजल के सारे ठीकानें लगभग बंद हो चुके है या रात के अंधेरे में चलाए जा रहे है। मगर बावजूद इसके एक माफिया जिले के लिए नासूर बना हुआ है। जिला गुजरात सीमा से सटा होने के कारण माफियाओं ने इसे अपनी काले धंधे की कर्मस्थली बना लिया था। पिटोल से लेकर ठेठ खजूरखो तक इन अवैध डीजल माफियाओं ने अपने पैर पसार लिए थे। इन माफियाओं को प्रशासन ने भी अपनी गोद में बैठाया और बहती गंगा में हाथ धोए। मगर लगातार अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के कारण प्रशासन दबाव में आया और अवैध डीजल माफियाओं के ठीकाने ऑफ द रेकार्ड बंद करवा दिए। ऑफ द रेकार्ड का मतलब सीधा सा है कि इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नही की गई। माफियाओं के इन अवैध डीजल बेचने के ठिकानों पर अब भी उनका तामझाम यथावत ही पड़ा हुआ है। अब तक प्रशासन ने इनके यह अवैध ठीये उखाड़ कर नहीं फैंके है। मतलब केवल अभी माफियाओं ने धंधा बंद किया उनके पंप मशीन, अवैध डीजल स्टॉक करने के टैंक और सभी व्यवस्थाएं अब भी यथावत ही है। इससे यह संभावना प्रबल बनती है कि भविष्य में इन्हे फिर से छूट दे दी जाएगी। प्रशासन व कलेक्टर के निर्देशन में हुई इस अंदरखाने की कार्रवाई में कुछेक माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया गयाजो जिले में लगातार सक्रिय है और जमकर चांदी काट रहे है।

सेटलमेंट के लिए भटकता फिर रहा युसूफ

वैसे तो बार्डर के समीप नेशनल हाईवे के किनारे पिटोल में टैंकरों से अवैध डीजल बेचने वाले माफियाओं की सक्रियता कम हो गई है, लेकिन युसूफ अब भी छोटे वाहनों से अवैध डीजल खपा रहा है। छोटे पीकअप टेंकरों से हाईवे पर गश्त करते हुए यह अपना धंधा चला रहा है। इसी युसूफ के बड़बोले पन ने प्रशासन की संदेहास्पद स्थिति की धज्जियां भी बिखेर कर रख दी है। युसूफ ने इस बात को भी सार्वजनिक कर दिया था कि, वह जिले के किन अधिकारियों कितने लाख की बंदी पहुंचाता है। अखबारों की सुर्खियों मे आने के बाद युसूफ के बड़बोले बोल ही उसके गले की हड्डी बन गए। अब हालात ऐसे है कि, युसूफ को दबे-छुपे धंधा करना पड़ रहा है। सेटिंग में एक्सपर्ट युसूफ की दाल अब जिले में गल नहीं रही है। अखबारों में मुद्दा उठने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी युसूफ को मीडिया सेटलमेंट की सलाह दे डाली और अब युसूफ प्रशासनिक दल्लों की इस रायशुमारी पर अमल करते हुए सेटलमेंट के लिए भटकता फिर रहा है। हालांकि युसूफ के पिटोल में टीक कर धंधा नहीं कर पाने का एक कारण पिछले दिनों पिटोल में हुआ हत्याकांड भी है। युसूफ ने पिटोल को छोड़ पिछले दिनों देवझिरी को अपना अवैध डीजल के कारोबार अड्डा बनाया था। देवझिरी के जीजे 3 ढाबे पर यह अपना अवैध करोबार चला रहा था। युसूफ को यहां सबसे बड़ा संरक्षण कृष्णा स्टोल क्रेसर के संचालक पटेल बद्रर्स का मिल रहा था। युसूफ के धंधे में आने वाली हर परेशानी को सुलझाने में पटेल ब्रदर्स का अहम रोल अब तक रहा है। मीडिया सेटलमेंट में भी युसूफ ने इन्ही का सहारा ले रखा है लेकिन दाल अब तक गली नहीं है।

अवैध धंधे का नहीं उतर रहा फितूर

पिटोल में ही होटल गुरूकृपा और होटल सागर के संचालक अज्जु-विज्जु की राजनीतिक पकड़ और हेकड़ी ढिली पड़ चुकी है। अवैध डीजल का कारोबार समेटते हुए इन्होने शराब के अवैध धंधे पर कॉन्संसट्रेट किया हुआ है। मगर सुत्रों के अनुसार इनके मन से अवैध डीजल का धंधा अभी पूरी तरह से गया नहीं है। नए ठिकानों की तलाश जारी है और छूट मिलते ही इनका यह कारोबार फिर से शुरू करने का इरादा है।अज्जू -विजू के अवैध धंधे का फितूर अभी उतरा नहीं है। अवैध तो अवैध है चाहे वह शराब हो या डीजल...?

चरित्र का दोगला और मुंह का मीठा माफिया रामपाल

पूरे जिले में अवैध डीजल के धंधे में सबसे संरक्षित और और सुरक्षित माफिया सोनू उर्फ रामपालसिंह चौहान ही साबित हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण उसका राजनीतिक बेकग्राउण्ड है। भाजपा अजजा मोर्चे में प्रदेश स्तरीय पद पर काबिज रामपाल अजजा मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष कलसिंह भाबर का खास गुर्गा है। पिछले दिनों कलसिंह भाबर को एक अखबार ने प्रदेश के गौरव के रूप में प्रकाशित किया था। मगर माफियाओं को इस तरह संरक्षण देना कलसिंह की छवि को 100 प्रतिशत धुमिल करने वाला ही है। राजनीतिक रसूख के कारण रामपाल पर अब तक प्रशासन भी हाथ नहीं डाल पाया है। या यूं कहने की रामपाल के आगे प्रशासनिक दल्ले नपुंशक ही साबित हुए है। एक तरफ जिले में अवैध डीजल का यह कारोबार बंद होता नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी और रामपाल का इस तरह खुलेआम अवैध डीजल का धंधा करना कई प्रश्न खड़े करता है। अपने आपको आदिवासियों का हितेषी बताने वाला रामापाल अब भी अपना अवैध डीजल पंप संचालित कर रहा है। चरित्र का दोगला और मुंह का मीठा रामपाल अपने राजनीतिक रसूख से प्रशासन को नपुंशक बनाकर अपने इस अवैध डीजल पंप से चांदी काट रहा है। प्रशासन का इस कदर संरक्षण यह सोचने पर मजबूर करता है कि, ''डीजल माफिया रामपाल से प्रशासन का यह रिश्ता क्या कहलाता है...?''

यहां पर रात के अंधेरे में हलचल

खजूर खो में संचालित हो रहे अवैध डीजल के ठिकानें को भी प्रशासन ने ऑफ द रेकार्ड बंद करवाया किंतू अवैध डीजल के इस ठीकानें पर रात के अंधेरे में हलचल बनी रहती है। खजूर खो में संचालित हो रहे इस अवैध डीजल के ठीकानें के मालिक चार पार्टनर है, जिसमें एक नाम रामपाल का भी बताया जाता है। रात के अंधेरे में चल रहे इस अवैध डीजल के ठीकाने पर भी रामपाल का पूरा संरक्षण है और सेटिंग के हिसाब से इसे रात में ही संचालित किया जा रहा है। हालांकि दिन के उजाले में यहां सन्नाटा पसरा पड़ा रहता है, लेकिन अवैध डीजल के इस ठीकाने पर रात में हो रही हलचल को बड़े वाहनों के टायरों के निशान दिन के उजाले में चीख-चीख कर दर्शाते है। रामपाल के छापरी स्थित और खजूरखो स्थित अवैध डीजल के यह ठिकाने जमकर माफियाओं की जेब भर रहे है। खजूरखो अवैध डीजल की खपत का सबसे बड़ा अड्डा है, नेशनल हाइवे के किनारे होने के कारण यहां से हजारों लीटर अवैध डीजल माफियाओं द्वारा खपाया जाता है।

प्रशासन की कार्यप्रणाली अब भी संदेहास्पद

अखबारों की सुर्खियों में मामला आने के बाद प्रशासन दबाव में जरूर है, लेकिन कहते है ना कि, दाढ़ में एक बार खून लग जाए तो उसका स्वाद लंबे समय तक जाता नहीं है। कुछ यही स्थिति जिले में अवैध डीजल माफियाओं को लेकर प्रशासन की बनी हुई है। प्रश्न तो यह भी उठता है कि गुप्त तरीके से इन डीजल माफियाओं पर कार्रवाई क्यों की जाती रही है। होने वाली कार्रवाईयों को सार्वजनिक क्यों नही किया जाता। ऑफ द रेकार्ड कार्रवाई के बाद प्रशासन माफियाओं के अवैध डीजल पंप क्यों उखाड़कर नहीं फैकता। इन अवैध डीजल पंपों पर पड़े सामानों की जप्ती क्यों नहीं करता। गुजरात से जिन वाहनों में यह डीजल अवैध रूप से वैक्स ऑइल के नाम पर लाया जाता है, उन्हे आज तक जांच कर जप्त क्योंनहीं किया जाता? यह वह सारे प्रश्न है जो जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अमले को संदेह के घेरे में लाते है।

अगले अंक में जयदीप बायो फ्यूल अंतरवेलिया की कहानी ''राजस्थान की पेकिंग में गुजरात का माल'' बायो डीजल के नाम पर चल रहा बड़ा खेल, झूठे मोहित पंडित का सारे दस्तावेज व कलेक्टर की अनुमति होने का दावा...।

माही की गूंज ट्रॉफी 2022 : क्रिकेट आयोजन का हुआ समापन

माही की गूंज, खवासा।

माही की गूंज क्रिकेट ट्राफी 2022 का आयोजन फेमस क्रिकेट क्लब खवासा के तत्वाधान में सम्पन्न हुआ। जिसमें थांदला, नारेला, कुशलगढ़, बामनिया, पेटलावद, करवड़, सुजापुरा, आदी 24 टीमों ने हिस्सा लिया और सभी मैच रोमांचक हुए। सेमीफाइनल में पहुचने वाली 4 टीम कुशलगढ़, इलेवन स्टार पेटलावद, फेमस क्लब खवासा ए, फेमस क्लब खवासा बी पहुँची।

जिसमे पहला सेमिफाइनल मैच फेमस क्रिकेट क्लब खवासा ए और फेमस क्रिकेट क्लब खवासा बी के बीच हुआ जिसमें फेमस क्लब खवासा ए ने बाजी मारी ओर फाइनल में जगह बनाई। वही दूसरा सेमीफाइनल इलेवन स्टार पेटलावद और कुशलगढ़ के बीच हुआ जिसमें इलेवन स्टार पेटलावद ने बाजी मारी ओर फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच सम्राट चोपड़ा रहे वही दूसरे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच प्रदीप डावर रहे। फाइनल मुकाबला इलेवन स्टार पेटलावद और फैमस क्रिकेट क्लब खवासा के बीच खेला गया, जिसमें इलेवन स्टार पेटलावद ने एक तरफा मुकाबले में फैमस क्रिकेट क्लब खवासा को 8 विकेट से हराया। इलेवन स्टार के गेंदबाज मनोज परमार फ़ाइनल के मेंन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 06 विकेट झटके।

बेस्ट बल्लेबाज कुशलगढ़ के सदाम को दिया गया, बेस्ट बॉलर मनोज परमार, मैन ऑफ द सीरीज सद्दाम, बेस्ट कैचर संजय व्यास, हैट्रिक ट्राफी ईशान मैंण को दी गई। प्रथम पुरस्कार माही की गूंज प्रधान संपादक संजय भटेवरा की और से 31131 रुपये तथा ट्रॉफी और द्वितीय पुरस्कार 21121 रुपये व ट्रॉफी खवासा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष तोलसिह गणावा द्वारा दिया गया।

आयोजन के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत चौपड़ा, माही की गूंज के प्रधान संपादक संजय भटेवरा, युवा जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह परिहार, पेटलावद के पार्षद लाला चौधरी, ब्रजभूषण परिहार, पत्रकार राकेश गेहलोत, प्रतापसिंह सिसोदिया, दीपेश भटेवरा उपस्थित रहे।

प्रत्योगिता के सफल संचालन में फैमस क्रिकेट क्लब के संजय व्यास, विनोद राठौर, गौरव चुण्डावत, सम्राट चौपडा, सुखराम मुणिया, रोशन पाटीदार, दिव्यम भगत, अक्कु पाटीदार, शैनेश पाटीदार(भौला), कपिल भगत, गिरीश पाटीदार, धर्मेन्द्र परमार, मोहित पाटीदार, छोटु चुण्डावत, मुकेश चौहान, अन्या चौहान, राजेन्द्र भगत आदि का योगदान रहा।

जामली सरपंच और सचिव ने योजना के लाभ के नाम पर विधवा महिला से ले ली राशि

मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान भी नही, सीईओ ने तुरंत निराकरण करने को कहा

माही की गूंज, पेटलावद।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजनाओं का लाभ देने के नाम पर सरपंच, सचिव की वसूली करना आम बात है, लेकिन किसी की मौत पर मिलने वाली राशि और मौत के बाद शासन द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि का लाभ दिलाने के नाम पर वसुली करने से भी नही चूक रह है। बुधवार को ग्राम जामली की बद्दू वसुनिया ने जनपद सीईओ अमित व्यास को आवेंदन देते हुए बताया कि, गत वर्ष अप्रैल में उसके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव ने संभल योजना का लाभ देने के नाम पर 5 हजार रुपये लिए ओर आज तक राशि का भुगतान नही करवाया। वही अंतिम संस्कार की राशि 5 हजार का भुगतान जो कि मौत के दिन ही शासन की और से किया जाता है उसका भुगतान भी नही किया गया। महिला का कहना है कि, वो ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जा चुकी हैं लेकिन पेंशन भी शुरु नही की गई। जनपद से जब रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि, अंतिम संस्कार की राशि के 5 हजार रूपए सचिव के खाते में जमा हो चुके हैं तो पीड़ित तक नही पहुँचे, शिकायत के बाद सीईओ अमित व्यास ने ग्राम पंचायत जामली के सचिव को तुरंत काल कर महिला से ली गई राशि का भुगतान करने और अंतिम संस्कार की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये है और कहा कि, इस प्रकार के कार्य करने वाले सचिवों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

खवासा पुलिस खो चुकी अपना जमीर, खा रही चौराहे पर जूते

माही की गूंज, खवासा।

खवासा पुलिस की ही बात करें तो माफियाओ और अपराधियों को संरक्षण देकर व गौ हत्या जैसे मामलों में भांजगाड़ी करने वाली पुलिस पूर्णतः अपना जमीर ऐसा खो चुकी है कि, पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं होने के साथ ही पुलिस का भय भी आम जनता में खत्म हो चुका है। नतीजन पुलिस अब चौराहे पर जूते खाते नजर आ रही है। जबकि पुलिस की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के साथ ही आम जनता में विश्वास और असामाजिक तत्वों, अपराधियों व माफियाओं में पुलिस का भय होना चाहिए, पर उसके उलट असामाजिक तत्वो, अपराधियों व माफियाओं में पुलिस का ऐसा विश्वास जमा की वे कुछ भी करे सब मामला निपट जाएगा, वही आम जनता में भय पुलिस बना चुकी है।

- जूते खाती हुई खवासा पुलिस।

- जूते खाने के बाद पुलिस आई हरकत में उदमादी को वाहन में जबरदस्ती ले जाती पुलिस।

बात करें खवासा की तो बुधवार को पुलिस के लिए अपने आप में कालिख पोत देने वाला दिन साबित हुआ। बाजना मार्ग पर खवासा चौकी पर पदस्थ पुलिस जवान जाम लगने पर यातायात व्यवस्था सुचारू कर रहा था कि, पुलिस से भय मुक्त शादी का बनोला निकालने वाले में शामिल युवकों से झड़प हो गई और युवक ने आव देखा न ताव, खाकी वर्दी धारी पुलिस को सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ टिका दिए। जब पुलिस पर आ बनी तो अपनी साक बचाने के लिए अन्य जवान को चौकी से बुलाकर पुलिस, युवक को जबरदस्ती उठाकर पुलिस के चार पहिया वाहन में बिठाकर ले गई और सार्वजनिक रूप से पुलिस पर हाथ उठाने पर नतीजा क्या होता है का प्रभाव बताने का प्रयास पुलिस ने किया।

पहले भी खा चुकी पुलिस जूते और जूते के 15 हजार लेकर मामला कर दिया रफा-दफा

बता दें कि, कुछ माह पूर्व ही खवासा चौकी के अंतर्गत ग्राम नारेला में भामल आ.जा. सह, संस्था के मैनेजर के पुत्र ईश्वर राठौड़ ने गांव में आए बारातियों के साथ हुज्जत की थी, मौके पर खवासा पुलिस पहुंची थी जहां पर भी ईश्वर राठौर व उसके उदमादी साथियो ने पथराव कर पुलिस व गाड़ी पर हमला करने के साथ ही एक एएसआई की कालर पकड़ ली थी। मामले में पुलिस इसी तरह ईश्वर राठौर एवं उसके उतमादी साथियों को चौकी में लेकर आई और लॉकअप में डालकर 2 दिन तक लट्ठ सुताई कर रखा था, जिसके बाद भामल के एक रिटायर्ड एएसआई की भांजगड़ी के साथ जूते खाने वाली पुलिस ने अपने जमीर को 15 हजार में आका और 15 हजार लेकर मामला रफा-दफा कर दिया।

अगर पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में अब भी सुधार नहीं लाती है तो आगे भी पुलिस ऐसे ही जूते खाऊं नजर आती रहेगी। आज के मामले में पुलिस क्या करती है जो आगे ही पता चलेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422